राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 36 अंक 7 अक्तूबर 2015 मूल्य 5 रु. पृष्ठ 36

लहराया भगवा

जनजाति छात्र-युवा संसद के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय जनजाति मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम का स्वागत करते हुए

छात्र संसद के उद्घाटन सत्र में संबोधित करती हुई केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी

पूर्वोत्तर छात्र-युवा संसद के समापन सत्र में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री किरण रिजीजू तथा अभाविप के पदाधिकारी

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक मण्डल

आशुतोष

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-23216298

ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com

ब्लॉग :chhatrashaktiabvp.com

वेबसाईट :www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी-50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली - 110007 से प्रकाशित एवं 102, एल. एस. सी., रिषभ विहार मार्केट दिल्ली-92 से मुद्रित।

संपादकीय कार्यालय

"छात्रशक्ति भवन"

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली - 110002

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
संपादकीय	4
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अभाविप का डंका	5
क्या कहते हैं डूसू पदाधिकारी	6
जेएनयू में अभाविप की वापसी, 14 साल बाद लहराया भगवा	7
साक्षात्कार	8
फिर छाया अभाविप का जादू – अभिषेक रंजन	10
भगवामय हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय	13
जनजातीय छात्रों का दिल्ली में समागम	14
छात्रा संसद में गूंजा शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, एवं स्वावलम्बन का मुद्दा	16
अभाविप की सराहनीय पहल, एक मंच पर आये पूर्वोत्तर के छात्रनेता	18
देश को समृद्ध बनाने में युवाओं की भूमिका अहम	19
विकसित भारत के स्वप्नदृष्टा : डॉ. कलाम – अवनीश राजपूत	20
हिन्दी दिवस के बहाने – डॉ. राजनारायण शुक्ल	22
विद्यार्थियों के प्रति गांधी जी के विचार	24
छोटे कद का दूरदर्शी फैसला, पलट दिया दुश्मन का मंसूबा – दीपक बरनवाल	25
पर्युषण पर्व के दौरान मीट बैन पर समीक्षा – उत्कर्ष श्रीवास्तव	29
राजनीति एवं कूटनीतिक तरीके से हो नेपाल में चल रही समस्या का निस्तारण	31
अभाविप ने कराया छात्राशक्ति का अहसास	32
भुवनेश्वर में अभाविप की महारैली	33
राष्ट्र निर्माण की चिन्ता करें युवा – श्रीहरि बोरिकर	34

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

गत लोकसभा चुनावों में मुंह की खाने के बाद हारे और बौखलाये सेक्युलरवादियों ने आस्था के विषयों को भी राजनैतिक दांव-पेच का हिस्सा बना लिया है। विडंबना है कि समाज को वैचारिक रूप से बंधक बनाने के इनके जाल में समाज का एक वर्ग भी फंसता जा रहा है। हाल ही में मांस बिक्री और गोहत्या के विषय को लेकर चले राजनैतिक घटनाक्रम ने जिस विद्रूप को जन्म दिया वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

पर्युषण पर्व के अवसर पर जैनमंदिर के सामने मांस की बिक्री करने जैसी ओछी राजनीति न अब तक देखी गयी और न सुनी गयी। इसी प्रकार काश्मीर में 1932 से चले आ रहे गोहत्या के कानून को चुनौती देते हुए हर चौराहे पर गोवध करने की चुनौती देकर राज्य के अलगाववादियों ने अपनी कुंठित मानसिकता का ही परिचय दिया। यह बात और है कि सरकार के कड़े तेवर के चलते उन्हें इसे कर दिखाने का अवसर नहीं मिल सका।

दोनों ही घटनाएं देश के दो अलग-अलग हिस्सों में होने के उपरान्त भी दो दृष्टियों से साम्य रखती हैं। पहला, राजनैतिक कारणों से समाज के एक हिस्से की भावनाओं को चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया गया। दूसरा, समाज के बीच से इन घटनाओं का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। वास्तव में, समाज से कोई प्रतिरोध न होने के चलते ही इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं।

उक्त घटनाओं को कानून-व्यवस्था की समस्या मान कर उसे हल करने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार पर छोड़ देना वस्तुस्थिति से नजरें चुराने जैसा है। कानूनी पहलुओं से कहीं बड़े प्रश्न सामाजिक सौहार्द और नैतिकता के हैं, जिनके हल खोजना समाज की जिम्मेदारी है। प्रशासन का काम प्रायः घटना होने बाद प्रारंभ होता है। ऐसी नौबत न आये, इसके लिये समाज में वातावरण उत्पन्न करने और बनाये रखने के लिये समाज को आगे आना होता है। आज इसी का अभाव है।

समाज में सदैव कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व सभी वाद-विवादों से ऊपर होता है। उनकी उपस्थिति किसी भी अशुभ की आशंका को टाल सकती है। लेकिन यदि मुंबई और श्रीनगर की घटनाएं हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि या तो समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों को मुख्य धारा से परे धकेल दिया गया है अथवा वे स्वयं थक कर किनारे बैठ गये हैं। दोनों ही स्थितियां समाज की दृष्टि से हानिकारक हैं।

दुर्भाग्य से यदि ऐसी स्थिति आ भी गयी है तो यह हाथ-पर-हाथ धर कर बैठने से ठीक नहीं होगी। किसी को तो इसके लिये पहल करनी होगी। यह पहल असंभव है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। भारत के उत्तर-पूर्व के राज्यों की जटिल स्थिति में से संवाद की पहल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन ने की है और उसे सफल कर दिखाया है।

हाल ही में दिल्ली में हुए उत्तर-पूर्व के छात्र-युवा नेताओं के सम्मेलन में अभाविप के निमंत्रण पर इन राज्यों के पचास से ज्यादा संगठनों के युवा नेता सम्मिलित हुए और एक स्वर से वहां के विकास पर जोर दिया। इनमें से अनेक संगठन ऐसे हैं जो अपनी नीतियों और विचारों में परस्पर विरोधी हैं, लेकिन अभाविप के मंच पर उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। ऐसे ही सम्मेलन छात्राओं और जनजाति छात्रों के भी हुए जिनमें बड़ी संख्या में देश भर से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उक्त सम्मेलनों के समाचार भीतर के पृष्ठों में मिलेंगे। इसके साथ ही दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित तमाम विश्वविद्यालयों में अभाविप ने छात्र-संघ चुनावों में जीत दर्ज की है जिनका विस्तृत विवरण इस अंक में संकलित है।

निवर्तमान राष्ट्रपति स्व. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के पश्चात आने वाला उनका पहला जन्मदिन देश के युवाओं के लिये प्रेरणा और संकल्प का अवसर है। इस अंक में उनको स्मरण करना तो कर्तव्य था ही, भोपाल में हुए अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन के विमर्श को भी संकलित कर विषय-वैविध्य का प्रयास हुआ है।

असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक-पर्व विजयादशमी और उसके बाद सुख और समृद्धि के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

आपका संपादक

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अभाविप का डंका

लगातार दूसरी बार चारों सीटों पर जीत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए चारों सीट पर जीत दर्ज की है। यह लगातार दूसरी बार है जब अभाविप ने कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) तीसरे स्थान पर रही। इस बार हुए चुनाव में 43.30 प्रतिशत छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डूसू में अभाविप के सतेन्दर अवाना, सनी डेढ़ा, अंजली राणा और छतरपाल यादव ने क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्ज की। अभाविप प्रत्याशियों ने नेशनल स्टुडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) और छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) के प्रत्याशियों को 4500 मतों से अधिक के अंतर से हराया।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी डी. एस. रावत द्वारा घोषित चुनाव नतीजों के अनुसार अध्यक्ष पद पर अभाविप के सतेन्द्र अवाना को 20,439 मत प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी एनएसयूआई के प्रदीप विजयरण को 6327 मतों के अंतर से पराजित किया है, विजयरण को मात्र 14,112 मत प्राप्त हुए। वहीं, अभाविप के सनी डेढ़ा ने उपाध्यक्ष पद पर सीवाईएसएस की गरिमा राणा को 7570 मतों के अंतर से पराजित किया। डेढ़ा को 19671 मत प्राप्त हुए, जबकि राणा को 12,101 मत मिली। सचिव पद के लिए अभाविप की अंजलि राणा ने एनएसयूआई के अमित सहरावत को 4610 वोटों के अंतर से हराया। अंजलि को 14,944 और सहरावत को 10,334 मत मिले। जबकि सीवाईएसएस के राहुल आर्य 7153 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर अभाविप के छतरपाल यादव को 16,243 वोट मिले और उन्होंने एनएसयूआई के दीपक चौधरी को 6065 मतों से हराया। इस पद पर आइसा के अभिनव 10,045 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे जबकि सीवाईएसएस की हितांशी 8205 मत प्राप्त कर चौथे स्थान पर रही। आपको बतादें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चार पदों पर 35 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। इस चुनाव में च्वाइस बेस्ड केडिट सिस्टम (सीबीसीएस) को वापस लिये जाने, सुरक्षा, विश्वविद्यालयों के छात्रों के परिवहन और आवास से जुड़ी समस्याएं हावी रहीं।

डूसू चुनाव में अभाविप को मिली शानदार जीत का जश्न पूरे देशभर में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में जीत की धूम रही। इतना ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखण्ड, हरियाणा–पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मिठाइयाँ बांटी गयी और सड़कों पर आतिशबाजियाँ छोड़कर कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जतायी।

■

क्या कहते हैं डूसू पदाधिकारी

अभाविप एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है जो पूरे साल छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए काम करता है। ऐसे में जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम छात्रों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठायेंगे और उसके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में सबसे पहले विश्वविद्यालय में प्रभावी तौर पर च्वाइस बेस्ड केडिट सिस्टम (सीबीसीएस) को लागू कराना है ताकि छात्रों को अपनी रूचि का आधार पर विषयों के अध्ययन की छूट हो। इसके अलावा, पूरक परीक्षाओं को फिर से शुरू कराने को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द ही इस पर भी निर्णय आ जायेगा। इसके अलावा, डीयू में नये कॉलेज खोले जाने को लेकर भी हमारी कोशिशें जारी हैं। - **सतेन्द्र अवाना, अध्यक्ष**

विद्यार्थी परिषद वर्ष भर अपने रचनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों के जरिए छात्र हितों के लिए संघर्ष करती रही है यही कारण है कि विश्वविद्यालय के छात्रों ने खोखले दावों और नारों को दरकिनार कर हमारे पैनल को चुना है। जब छात्रों ने अपना विश्वास हम पर दिखाया है तो उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मेट्रो में रियायत मिले या फिर पास की व्यवस्था हो, इसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, साथ ही और अधिक संख्या में यू-स्पेशल बस चलाने तथा विश्वविद्यालय में रेलवे आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। - **सन्नी डेढ़ा, उपाध्यक्ष**

डीयू में देशभर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं लेकिन छात्रावासों की कमी की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में छात्र-छात्राओं को छात्रावास की उचित सुविधा मिले, इस पर हमारा प्रमुखता से ध्यान रहेगा। इसके अलावा रूम रेन्ट कंट्रोल एक्ट और पीजी रेग्यूलेशन एक्ट के जरिए विश्वविद्यालय से बाहर रहने वाले छात्रों को उचित मूल्य पर कमरा मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हम दिल्ली विश्वविद्यालय कैम्पस में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, परिसर के एक सड़क का नाम 'निर्भया मार्ग' रखने के लिए भी विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। - **अंजलि राणा, सचिव**

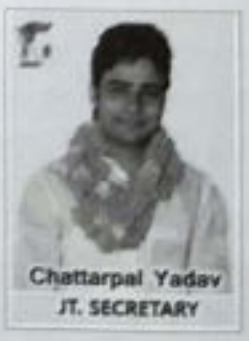

हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर शिक्षा से जुड़े वे सभी काम हैं जो छात्र हितों से जुड़ें हैं। विश्वविद्यालय का शैक्षिक माहौल और भी अधिक प्रभावी हो इसके लिए हम प्रवेश, परीक्षा और परिणाम में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनायेंगे। कैम्पस में वाई-फाई और इंटरनेट की बेहतर सुविधा, प्रयोगशाला में कम्प्यूटर और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता तथा कॉलेज में उचित सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाये, इनको लेकर भी हम प्रयासरत है। - **छत्रपाल यादव, सह सचिव**

जेएनयू में अभाविप की वापसी, 14 साल बाद लहराया भगवा

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव पद जीतकर 14 साल बाद वापसी की। अभाविप के सौरभ कुमार शर्मा ने आइसा प्रत्याशी हामिद राजा को कड़े मुकाबले में मात देते हुए यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके अलावा अभाविप ने अपने मत प्रतिशत में भी जबरदस्त बढ़ोत्तरी की। उपाध्यक्ष और सचिव पद पर भी अभाविप उम्मीदवारों ने वामपंथ समर्थित प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देते हुए उपविजेता का गौरव हासिल किया है। वहीं, अभाविप ने विभिन्न स्कूलों में 11 काउंसिलर की सीट जीतने के साथ अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (एसआईएस) में भी 11 वर्ष बाद एक सीट पर जीत दर्ज की है। इससे पहले, सेन्ट्रल पैनल में अभाविप ने वर्ष 2001 में जीत हासिल की थी, तब संदीप महापात्रा एक वोट के अंतर से अध्यक्ष पद पर विजयी हुए थे।

विदित हो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) से संबद्ध ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष और महासचिव के पद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की झोली में गए हैं। ये पद क्रमशः शेहला रशिद शोरा और राम नागा ने जीते हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के सीईसी प्रवीण थपलियाल ने बताया, अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले एआईएसएफ के कन्हैया कुमार को कुल 1029 मत मिले और उन्होंने आईसा के विजय कुमार को 67 मतों से पराजित किया। उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर आईसा प्रत्याशी शेहला रशिद और रमा नागा को क्रमशः 1,387 और 1,159 मत मिले और उन्होंने अभाविप के प्रत्याशी वेलंटीना ब्रह्मा और देवेंद्र सिंह राजपूत को हराया। संयुक्त सचिव पद पर जीतने वाले अभाविप के सौरभ कुमार शर्मा ने आईसा के हामिद रजा को 28 मतों से पराजित किया। जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव में 53.3 फीसदी मतदान हुआ था, जिसमें पिछले साल की अपेक्षा मामूली गिरावट देखी गई है। पिछले साल 54.58 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार छात्र संघ के केंद्रीय पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे।

छात्रशक्ति प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए सौरभ शर्मा ने कहा, मुझे खुशी है कि अभाविप ने 14 साल बाद जेएनयू में वापसी की है। इसका पूरा श्रेय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और जेएनयू के छात्र–छात्राओं को जाता है जिन्होंने हमारे राष्ट्रवादी विचार को समर्थन देते हुए हमें इस पद के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जीत का भरोसा था, क्योंकि हम छात्र हितों के लिए पोस्टरों पर नहीं बल्कि जमीन पर संघर्ष करते हैं। मैं जेएनयू के छात्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। सौरभ शर्मा ने कहा कि वह महिलाओं की सुरक्षा और नए छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता देंगे। ■

साक्षात्कार

वामपंथियों के गढ़ में सेंध लगाने वाले अभाविप प्रत्याशी सौरभ शर्मा

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में सभी को चौंकाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथियों के गढ़ में परचम लहराया है। 14 साल बाद छात्र संघ चुनाव में अभाविप ने एक सीट पर जीत कर जेएनयू में वापसी की है। यह जीत इसलिए भी और बड़ी हो जाती है क्योंकि जेएनयू वामपंथी छात्र संगठनों का गढ़ रहा है। बहरहाल, इस वर्ष अभाविप के सौरभ शर्मा ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत हासिल कर ली है। सौरभ शर्मा से बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि अमित चौहान ने। प्रस्तुत हैं साक्षात्कार के प्रमुख अंश....

चौदह साल के बाद जेएनयू में विद्यार्थी परिषद की वापसी हुई है। इसका श्रेय आप किसे देंगे ?

सबसे पहले में जेएनयू इकाई के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही हमारे सभी वर्तमान तथा पूर्व कार्यकर्ताओं का भी.. जिनके अथक प्रयासों के कारण हमें सफलता मिली है। ये जीत हमारी राष्ट्रीय विचारधारा की जीत है। हमारे मुद्दों की जीत है जिसे हम छात्रों के बीच लेकर गए थे।

जेएनयू की जीत को लेकर आपने क्या तैयारियां की थीं ?

हम गत दो–तीन वर्षों से काफी मेहनत कर रहे थे। कार्यक्रम करने के साथ ही छात्रों के मुद्दे उठाते रहे। हम मुख्य पदों पर न होते हुए भी तमाम कार्य करवाते रहे। हमने ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) की राशि बढ़वाई। हमने एम–फिल, पीएचडी की सीटों के लिए लड़ाई लड़ी। हमने केंद्रीय मंत्री से मिलकर जेएनयू में गैस पर सब्सिडी दिलाई, जिससे मेस का बिल कम आने लगा। ऐसे तमाम कामों के बाद छात्रों ने सोचा कि अगर अभाविप यूनियन में न होकर भी इतना काम करा रही है, तो वो यूनियन में होती तो कितना काम कराती।

काम ही मुद्दा होता तो क्लीन स्वीप क्यों नहीं कर गई अभाविप ?

आप जानते ही हैं, यहां एडमिशन के तुरन्त बाद छात्रों का ब्रेनवाश कर उन्हें दल विशेष से जोड़ लिया जाता है। फिर भी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हम बहुत कम अंतर से अपनी अन्य सीटें हारे हैं। अगले साल जीत और बड़ी होगी।

जीत की वजह परिषद की मजबूती या लेफ्ट पाटियों की कमजोरी?

हम कई सालों से छात्रों के मुद्दों को लेकर काम कर रहे है। लेफ्ट पार्टियां दुष्प्रचार करके छात्रों को बहकाती रही है। इस भ्रम को हम तोड़ने में कामयाब हुए है। हमने वादे किये और निभाए भी है। जैसे– एसआरएफ–जेआरएफ में बढ़ोतरी, लड़कियों के कॉमन रूम की समस्या, 24X7 पुस्तकालय जो पांच बजे बंद हो जाती थी। ऐसे ही कैम्पस के कई मुद्दे है जिन्हें लेकर हम काम करते रहे है। इसलिए जेएनयू के छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर विश्वास जताया है।

जेएनयू में वामपंथी होना फैशन रहा है। अब परिस्थितियां कैसी है?

कैम्पस में वामपंथ कोई फैशन नहीं रहा है, छात्र मजबूर होकर ऐसा करते थे। कैम्पस में भैय्या और दीदी की व्यवस्था रही है। वामपंथी नए छात्रों को अपने कमरे में जगह देते थे, ना चाहते हुए छात्रों को उनकी बातों को मानना होता था। मगर अब ये व्यवस्था टूट गई है।

छात्रों के लिए अब क्या प्राथमिकताएं हैं ? किस तरह के काम कर छात्रों का भला करेंगे ?

परिषद आधारित कार्य हम पहले से ऐसा करते आए है। लेकिन अब जिम्मेदारी मिलनें के बाद हम छात्रों की समस्या को लेकर अधिक कार्य करेंगे। हम

यातायात, वाई–फाई, छात्रावास को लेकर काम करेंगे तो सफाई और स्ट्रीट लाइट्स हमारा अन्य मुद्दा रहेगा। वहीं पुस्तकालय में नई किताबों को मंगाने के साथ ही हिंदी के संदर्भ पुस्तकों की भारी कमी को भी पूरा करवाएंगे। साथ ही छात्रों को जो नाममात्र का अनुदान मिलता है, उसे भी बढ़वाने की कोशिश करेंगे। छात्रों के लिए खेल को लेकर सुविधाओं के नाम पर पुरानी चीजें हैं, स्पोर्ट्स किट खत्म हो चुकी हैं। हम केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का ख्वाब लेकर आते तो हैं पर यहां मिलने वाली सुविधाओं से निराश होते हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन का अलख जगायेंगे।

जेएनयू में प्लेसमेंट एक बड़ी समस्या है ?

जेएनयू में प्लेसमेंट को लेकर आवाज अभाविप उठाती रही है। परिषद के प्रयास से ही कैम्पस में प्लेसमेंट प्रकोष्ठ बना था, लेकिन फिलहाल यह प्रभावी नहीं है। पिछले वर्ष प्लेसमेंट कंपनियां आई लेकिन वाम समर्थित पार्टियों और जेएनयू अध्यक्ष ने उन्हें काम करने नहीं दिया। लेकिन इस वर्ष से हमारा प्रयास रहेगा कि हम कैम्पस में प्लेसमेंट बेंच लगवाए।

जेएनयू में छात्रावास भी एक बड़ा मुद्दा रहा है ?

वर्ष 1986 में जब अभाविप पैनल में आयी तब जाकर लोहित, चंद्रभागा और ताप्ती छात्रावास का निर्माण हुआ। वर्ष 2000 में परिषद के प्रयासों से हेल्थ सेंटर, रेलवे आरक्षण केंद्र और डीटीसी का सेंटर कैम्पस में बना। रही बात छात्रावास समस्या की तो इसकी फाइल रूकी हुई है और हमारी कोशिश है कि यह काम भी जल्द हो जाए।

कैम्पस में संगठनात्मक रूप से काम करने और विचार परिवार के संगठनों को साथ लाने की जरूरत लगती है क्या ?

कैम्पस में हमें संगठनात्मक रूप से और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। रही बात विचार परिवार के संगठनों की तो वो कांउसिंल की बैठक में हमें उनका पूरा सहयोग मिलता है। चाहे मुद्दा राष्ट्रीय हो या कैम्पस से जुड़ा हमें उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। ■

मांगों को लेकर अभाविप ने घेरा कुलपति कार्यालय

रोहतक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अंक घोटाले को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड कर सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की।

अध्यक्ष प्रवीण राणा व छात्र नेता राकेश सांगवान ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि विद्यार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विश्वविद्यालय में कभी छत पर उत्तर पुस्तिकाएं मिलती है तो अब शून्य से 55 अंक कर दिए गए है। यह सब परीक्षा नियंत्रक की नाक के नीचे हो रहा है। इस अंक घोटाले से केवल प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तो मात्र केवल कर्मचारियों को सस्पेंड कर पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिषद कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे घोटाले से संबंधित सभी दस्तावेज कुलपति अपने कब्जे में ले व परीक्षा नियंत्रक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच भी कराई जाए। अभाविप ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक व अन्य सभी आरोपियों को सस्पेंड नहीं किया गया तो परिषद जल्द ही चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। वहीं, अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कुलपति ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

फिर छाया अभाविप का जादू

राष्ट्रवाद की अलख को मिला युवाओं का समर्थन

✍ अभिषेक रंजन

असम के नौगांव से लेकर देहरादून के डीएवी कॉलेज तक, दिल्ली के जेएनयू से लेकर पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक, विद्यार्थी परिषद् ने इस वर्ष देश के हर कोने में हुए छात्र संघ चुनाव में अपना परचम लहराया है। इसमें बेहद खास रहा दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू का छात्र संघ चुनाव। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार चारों पदों पर कब्जा जमाया, वहीं जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में 14 वर्षों के बाद सेंट्रल पैनल में जगह बनाते हुए परिषद् के उम्मीदवार सह सचिव के पद पर विजयी रहे। वामपंथियों के गढ़ कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय में परिषद् की जीत ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं। राजस्थान और पश्चिम बंग सहित कई ऐसे भी शैक्षणिक परिसर रहे, जहाँ छात्र संघ चुनाव में पहली बार भगवा लहराया तो कहीं वर्षों बाद यूनियन में वापसी की।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर पूरे देश की नज़र रहती है। इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय था, जिसमें नौटंकी की राजनीति का प्रतीक 'आप' की छात्र इकाई भी शामिल थी। आप की सरकार द्वारा धन–बल के इस्तेमाल की केवल सीमाएं ही नहीं लांघी गई बल्कि झूठे सर्वे और फरेबी लुभावने वादों के जरिये विद्यार्थियों को भरमाने की पुरजोर कोशिश भी की गयी। मगर सारी कोशिशें बेकार गई और विद्यार्थियों ने जीत का सेहरा न केवल परिषद् उम्मीदवारों के सर बांधा बल्कि अपाई राजनीति को सिरे से नकारने का भी काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सचिव पद पर विजयी अंजली राणा के शब्दों में, महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर केजरीवाल की गन्दी राजनीति को न केवल विद्यार्थियों ने नकारा बल्कि इस जीत ने सुरक्षित परिसर बनाने के हमारे प्रयासों को और ताकत दी। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह जीत हमें

दिल्ली विश्वविद्यालय के उन समस्यायों से लड़ने में बड़ी ताकत बनेगी, जिनसे यहाँ के विद्यार्थी वर्षों से जूझ रहे हैं।

जेएनयू में पिछले वर्ष बहुत कम अंतर से परिषद् के उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सके थे, इस बार ना केवल मत–प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई बल्कि एक सीट अपनी झोली में भी डालने का काम किया। बाकी सीटों पर हार मामूली अंतर से मिली। लेकिन सिर्फ सौरभ शर्मा की जीत की सुरभित सुगंध लाल–दुर्ग से पूरे देश में फैली और आज ना केवल जेएनयू बल्कि देशभर से जुड़े कार्यकर्ताओं का उत्साह इस जीत के बाद देखते बनता है। यह बिना डरे, लगातार लड़े और राष्ट्रविरोधी ताकतों के विरुद्ध जमकर अड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। सौरभ की माने तो यह चुनावी परिणाम यह बताने के लिए काफी है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी करने वाले व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों के हितैषियों को प्रबुद्ध विद्यार्थी नकारने लगा है। पूरी उम्मीद है, अगले वर्ष जेएनयू की यूनियन पर सिर्फ ज्ञान–शील–एकता का सन्देश लिए परिषद् का झंडा ही लहराएगा।

लोकतंत्र की पहली पाठशाला के इस चुनावी नतीजे के अपने मायने हैं। परिषद् एक विचार को लेकर काम करती है, जिसका एकमेव लक्ष्य राष्ट्रवादी विचारों से युवाओं को जोड़ना और उन्हें देशहित में जीने और मरने हेतु दिशा प्रदान करना है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक रूप से देश के काम आए, ऐसी कोशिशें विभिन्न तरह के रचनात्मक व आंदोलनात्मक गतिविधियों के जरिए शैक्षणिक परिसरों में कार्यकर्ता करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, लद्दाख से लखनऊ तक, दिन–रात इसी लक्ष्य के साथ अनेकोनेक कार्यकर्ता अनवरत और बिना किसी विश्राम की चिंता किये करते रहते हैं। कइयों ने तो अपनी जवानी ही नहीं, पूरी जिन्दगी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगा दी। छात्र संगठन के नाते हर साल एक नई पीढ़ी परिषद् से जुड़ती है और एक पीढ़ी परिसरों से निकल अपने–अपने क्षेत्र में जाकर परिषद् के विचारों व सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती है। छात्र संघ चुनाव व उसके परिणाम कभी परिषद् के कार्य का मुख्य उदेश्य नहीं रहा। यह इसके कार्य का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन इन चुनावों के माध्यम से समाज में परिषद् के संगठन की शक्ति व इसके कार्य का अंदाजा समाज लगाता है। स्वाभाविक है, छात्र संघ चुनावों में देशभर से मिले बेहतर परिणाम कार्यकर्ताओं के लिए ना केवल उत्साहवर्धन का काम करते हैं, बल्कि इस कार्य को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए अनुकूलता भी प्रदान करते हैं। यह जीत भी कुछ वैसी ही थी।

छात्र संघ चुनावों के परिणामों के पैटर्न को देखे तो दो बातें साफ नज़र आती हैं। पहली, जहाँ विद्यार्थी परिषद् जीतती रही है, कमोवेश उन सभी जगहों पर परिषद् के उम्मीदवार इस बार फिर चुनकर आये हैं। दूसरी, जहाँ परिषद् अब तक जितने में कामयाब नहीं हो पायी थी या फिर जिन जगहों पर कभी बेहतर कार्य था और कालांतर में किन्ही वजहों से संगठन कमजोर हुआ, उन जगहों पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चुनावी फतह हासिल हुई। विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरी बोरीकर की माने तो यह जीत महज यूनियन में परिषद् उम्मीदवारों का स्वीकार्यता भर नही है, बल्कि विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं की सक्रियता व छात्र–विरोधी संगठनों के विचारों के अस्वीकार्यता का प्रतिक भी है। देशभर में मिली शानदार जीत यही साबित करती है कि देश के युवाओं ने जहाँ राष्ट्रवादी शक्तियों से जुड़ने की इच्छा जताई है, उसे समर्थन दिया वहीं, देशविरोधी संगठनों को उसने नकारने का भी काम किया है। नये–नये स्थानों पर जीत संगठन के प्रति बढ़ता विश्वास और छात्रों की समस्या के समाधान को लेकर किए अनवरत संघर्ष का परिणाम है। यह इस बात का परिचायक भी है कि परिषद् ने दूसरे संगठनों की राह पर ना चलते हुए छात्र आन्दोलन को जिन्दा रखा है। उसके नये–नये पहल का स्वागत विद्यार्थियों ने किया है और आज उसी का परिणाम है

कि परिषद् के विचार की स्वीकार्यता बढ़ी है। एक तरफ जहाँ अन्य छात्र संगठन महज विरोध के लिए विरोध करते रहे, वहीं परिषद् ने ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे जरूरी सुधारों का समर्थन किया बल्कि उसमें कमियों को भी ठीक करने का काम किया। युवाओं से जुड़े विषयों पर अलग–अलग कार्य करके जैसे थिंक इंडिया, उत्तर–पूर्वी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अलग प्रकल्प अंतर–राज्य छात्र जीवन दर्शन (SEIL), परिसरों में नियमित रोजगार मेला, कौशल विकास जैसे विषयों पर काम करके इसे सभी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सर्वग्राही बनाया, जिससे संगठन लगातार सर्वव्यापी होता जा रहा है।

इन सबके बावजूद छात्र संघ चुनाव में मिली सफलता ने बाकी चीजों के अलावा एक और जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं पर ला दी है, वह है अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। परिषद् हर बार इस अपेक्षा पर खरा उतरती रही है लेकिन अब उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। जिसमें छात्र संघ के पारंपरिक तौर तरीके को और ज्यादा स्टूडेंट्स–फ्रेंडली बनाना है, बल्कि विद्यार्थियों को वैचारिक रूप से ही नहीं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी एक सक्षम नागरिक बनाना है। देशभर के छात्र संघ संघर्ष के साथ–साथ विद्यार्थी हित में करियर काउंसिलिंग, व्यक्तित्व विकास, जरूरतमंद को आर्थिक सहायता, परिसरों को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए लगातार रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना भी अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर की सक्रियता ही परिषद् की विश्वसनीयता है, हम उसे बाकियों के लिए रोल–मॉडल बनाएं। छात्र हितों से जुड़े छोटे–बड़े सभी मुद्दों को लेकर समाधानपरक निर्णायक संघर्ष करें और इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि छात्र–संघ सिर्फ खेल और सांस्कृतिक समितियों तक सीमित ना रहकर, विद्यार्थियों की छोटी–बड़ी समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न तरह की गतिविधियाँ नियमित करने के साथ शैक्षणिक परिसरों के विकास में अपना व अपने विचारों के अनुकूल योगदान देने के लिए एक दूरदर्शी विचारों के साथ काम करे। स्वच्छ भारत अभियान और नशा मुक्त परिसर बनाने की उसकी मुहीम से समाज के एक बड़े वर्ग में "परिषद् कार्यकर्ता इस कार्य को करने के लिए सबसे आदर्श है" की भावना जगी है। लोगों को पता है कि 'नशा मुक्ति' सिर्फ नारा नहीं है बल्कि अधिकांश कार्यकर्ताओं की जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। कार्यकर्ता छात्र संघ के साथ वर्ष भर सक्रीय रहें और इसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों में दिखे, भौतिक व वैचारिक रूप से परिसर स्वच्छ दिखे, सुन्दर लगे, इस हेतु सक्रीय रहकर ही परिषद् के विचार और छात्र संघ के उदेश्य की प्राप्ति कर सकेंगे। विश्वास है, इसी तरह आनेवाले वर्षों में जीत का सिलसिला जारी रहेगा। परिसरों को बेहतर बनाने, रोजगारमूलक प्रयास करने व छात्र–हितों के लिए सक्रीय रहकर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़कर छात्र संघ में प्रतिनिधि जीते, उसे पूरा करने में अपनी ऊर्जा लगायेंगे। ■

अभाविप का मोबाइल ऐप

डाउनलोड

करने की लिंक आपको

ABVP के

अधिकारिक अकाउंट

http://www.facebook.com/ABVPVOICE

https://twitter.com/abvpcentral

पर और वेबसाइट

www.abvp.org

पर भी उपलब्ध रहेगी।

भगवामय हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय

पांच में से चार सीटें अभाविप की झोली में

इलाहाबाद। दिल्ली हो या देहरादून... पूर्वोत्तर हो या प्रयाग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगभग सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में अपना परचम लहराया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में इस बार अभाविप के खाते में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। यहां पांच में से चार सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए अभाविप ने अनोखा रिकार्ड बनाया है। आपको बतादें कि विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी संगठन के पैनल को इतने पदों पर जीत हासिल हुई हो। अध्यक्ष पद छोड़कर शेष सभी चार पदों उपाध्यक्ष, महामन्त्री, संयुक्त सचिव और सांस्कृतिक सचिव पद पर अभाविप काबिज हुई है।

स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरी ऋचा सिंह ने इतिहास रचते हुए आजादी के बाद पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा के चुने जाने का गौरव हासिल किया। ऋचा सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11 वोटों से हराया। समाजवादी छात्र सभा का समर्थन प्राप्त ऋचा को कुल 2253 वोट मिले। वहीं 2242 वोटों के साथ रजनीश कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे। महामंत्री पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सिद्धार्थ सिंह ने बाजी मारी। सिद्धार्थ को कुल 2636 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर अभाविप प्रत्याशी विक्रांत ने जीत दर्ज की, विक्रांत के खाते में 1994 वोट आये। जबकि सांस्कृतिक सचिव पद पर अभाविप प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को जीत मिली। जितेन्द्र को 2378 वोट मिले, इसके अलावां संयुक्त सचिव पद पर भी अभाविप उम्मीदवार सरवन कुमार जायसवाल ने 1777 वोटों के साथ जीत हासिल की।

अपने चारों मजबूत दावेदारों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। यह विद्यार्थी परिषद का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और वामपंथी संगठन आईसा एवं एसएफआई के साथ ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई समाजवादी छात्र सभा भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पायी। ■

संसद

जनजाति छात्रों का दिल्ली में समागम, शिक्षा व रोजगार के मुद्दों पर हुआ मंथन

19 प्रदेशों के 200 से ज्यादा जनजातीय छात्रों-युवाओं का लगा जमघट

उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अखिल भारतीय जनजाति कार्य प्रमुख श्री प्रफुल्ल आकांत तथा मंचासीन मान्यवर

नई दिल्ली। जनजाति समाज के लोग कई मुद्दों पर अन्य लोगों से काफी भिन्न हैं। इनकी वर्षों पुरानी अपनी संस्कृति, परम्परा और रहन–सहन है, जिसे आज भी ये बचाकर रखे हुए हैं। आज आवश्यकता है कि जनजाति युवा आगे बढ़कर देश की मुख्य धारा में काम करें और जनजाति क्षेत्रों में संतुलित विकास हो। यह बातें में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित जनजातीय छात्र युवा संसद में छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने जनजाति युवाओं से देश के विकास के लिए कार्य करने की अपील की और अपनी भाषाओं को बचाने का उनसे आह्वान भी किया। साथ ही, श्री जुएल ओराम ने भारतीय जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और सामाजिक–संरचना पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार द्वारा जनजाति समाज के लिए पारित बजट व योजनाओं का उल्लेख किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनसीडीएनटी के अध्यक्ष श्री भिकू इदाते ने कहा कि अभाविप देश से विदेश पर्यन्त विचार करने वाला छात्र संगठन है। इसके बेहतर प्रयास का ही नतीजा है कि जनजातीय समाज के लोगों को अपनी बात रखने का इतना बड़ा मंच मिल सका। जनजातीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि शहरी लोग शिक्षित जरूर है पर सुसंस्कृत नहीं, जबकि जनजातीय लोग सुसंस्कृत है पर शिक्षित नहीं।

वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरि बोरिकर ने 'समाज में युवाओं की भूमिका' पर प्रकाश डालते हुए छात्रशक्ति को राष्ट्रशक्ति बनाना, देशी–विदेशी युवाओं की आर्थिक समस्याओं और विकासार्थ विद्यार्थी (SFD) के द्वारा छात्र समाज की समस्याओं को दूर करने की बात की।

इस संसद के उद्घाटन सत्र में अभाविप के अखिल भारतीय जनजातीय प्रमुख प्रफुल्ल आकान्त ने भारत के विभिन्न 'जिलों में जनजातीय लोगो की संख्या की तुलना में शिक्षा संस्थानों व स्वास्थ्य सेवाओं में कमी

का उल्लेख करते हुए युवाओं के कौशल विकास पर बल देने की बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का यह कदम बहुत ही आवश्यक था, जो जनजाति छात्रों के सम्पूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि लगभग 150 जिले जनजाति बहुल हैं, इन क्षेत्रों में वन, जल, खनिज सम्पदा बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। आज मूल प्रवाह में जनजातीय समाज को लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जनजातीय महापुरुषों को पाठ्यक्रम में स्थान भी मिलना चाहिए। श्री प्रफुल्ल आकान्त ने भारत की जनसंख्या को सकारात्मक दृष्टि से देखने की बात करते हुए कहा कि जनसंख्या कोई समस्या नहीं है बल्कि जनसंख्या हमें शक्ति का बोध कराती है।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आम्बेकर ने कहा कि इस देश में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाना विद्यार्थी परिषद का काम है। यह समाज अकेला नहीं है अपितु पूरा परिषद परिवार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का पेटेंट जनजाति समाज के पास है, अतः जनजाति लोक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जिसस जनजाति लोगों की सहभागिता भी बढ़ेगी।

अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री के. एन. रघुनन्दन ने अपने उदबोधन में कहा कि अंग्रेजों के आने के बाद से ही जनजाति समाज की उपेक्षा हुई है, ऐसे में इस स्थिति में परिवर्तन कर समाज की मुख्य धारा से इन्हें जोड़ने का काम हमें ही करना है। इसके अलावा, रोजगार मांगने की जरूरत के बजाय हमें रोजगार सृजन की ओर ध्यान देना चाहिए, इससे सभी को अपने हिसाब से काम करने का मौका मिलेगा और बेरोजगारी भी घटेगी। उन्होंने शिक्षा में बदलाव की अनिवार्यता को बताते हुए जनजातीय जीव को शोध का विषय बनाये जाने पर भी बल दिया। साथ ही कहा कि जनजाति समाज के प्रबुद्ध लोग भी अपने आनुभतिविक सुझावों को समय–समय पर सरकार से साझा करें।

जनजातीय छात्र संसद में छात्रों को सम्बोधित करते हुए डा. मनरूप सिंह मीणा ने कहा कि जनजातीय संस्कृति समृद्ध संस्कृति है किन्तु कालान्तर में शिक्षा का स्तर, रोजगार तथा जनजातीय संस्कृति का स्तर निम्न हुआ है। युवाओं के योगदान एवं उनकी भूमिका से इन क्षेत्रों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा, डा. मीणा ने बताया कि भारत के इतिहास में जनजाति समाज का गौरवपूर्ण स्थान है। हम सभी जानते हैं कि सम्पूर्ण भारत में लगभग 20 फीसदी जनजातीय क्षेत्र एवं देश की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातीय समाज का ही है।

वहीं, डा. गिरीश प्रभुणे ने ज्ञान की महत्ता बताते हुए कहा कि रोजगार के लिए डिग्री नहीं अपितु ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे में जनजाति समाज में जो ज्ञान का भण्डार है उसके संरक्षित करने के लिए विद्यालय होना चाहिए। जिसमें जनजातीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम शामिल हो तथा कौशल के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाये।

इसी क्रम में श्री कौल नेगी ने जनजातीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर विषय पर कहा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता है तथा कौशल विकास शिक्षण–प्रशिक्षण द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुहआ, इमली जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र में कृषि आधारित व्यवसायिक संस्थाओं के साथ हर्बल इण्डस्ट्री को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

अभाविप द्वारा एनडीएमसी सभागार, दिल्ली में आयोजित 'जनजातीय छात्र–युवा युवा संसद' में 19 प्रदेशों के 248 छात्र–छात्रा व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एवीबीपी द्वारा इस प्रकार का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें देश भर से युवा अपने समाज के विषय में चिंतन करने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए है। इस संसद के अंत में छात्रों द्वारा जनजाति विकास हेतु कुछ प्रस्ताव पारित किये जायेंगे, जिन्हें भारत सरकार को सौंपा जायेगा। ■

संसद

छात्रा संसद में गूंजा शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान एवं स्वावलम्बन का मुद्दा

देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों छात्राओं ने की शिरकत

उद्घाटन सत्र में मंच पर केन्द्रीय मंत्री महिला व बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी। साथ में अभाविप पदाधिकारी।

नई दिल्ली। समाज में महिलाओं को आगे बढ़कर अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार भी महिला सशक्तिकरण हेतु गंभीरता से काम कर रही है, और अपने एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाये हैं। ऐसे में महिलाओं को स्वयं भी आगे आकर सरकार से अपने अधिकार की बात करनी चाहिए तथा समाज में अपनी भूमिका पर विचार भी करना चाहिए। उक्त बातें केन्द्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने अभाविप द्वारा आयोजित छात्रा संसद में छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहीं।

मेनका गांधी ने छात्राओं का आह्वान करते हुए अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने इस बार 1400 महिलाओं को नियुक्ति दी है, ऐसा काम अन्य राज्यों के द्वारा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण होना चाहिए। हर फोन में एक पैनिक बटन जीपीएस कनेक्टीविटी के साथ होनी चाहिए ताकि आपातकाल में महिलाएं उसका प्रयोग कर सकें। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। छात्रा संसद में श्रीमति गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अब सरकार हर गाँव में एक एसएमपीओ (स्पेशल महिला पुलिस ऑफिसर) को नियुक्त करेगी जो पुलिस और वहाँ की महिलाओं के बीच इंटरफेस की भूमिका अदा करेगी। उन्होंने अभाविप द्वारा छात्रा संसद के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्राओं में नेतृत्व का विकास होगा।

अभाविप की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने देशभर से आई छात्राओं को अपने क्षेत्रों में महिलाओं

का नेतृत्व करने का आह्वान किया। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने देशभर से आयी छात्राओं को डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में इस बार अभाविप की जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं को स्वयंसिद्धा बनकर स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।

मुम्बई से आयी हुईं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री गीता गुण्डे ने कहा कि आज समाज में पुरुषों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भी महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। शुरू से ही महिला सबला रही है। हमें अपनी शक्ति को पहचानते हुए सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका का प्रभावी निर्वहन करना चाहिए। इस सत्र में विभिन्न राज्यों से आयी हुई छात्राओं ने अपने राज्यों की महिलाओं से सम्बंधित विषयों पर अपनी बात रखी।

इस दौरान, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए लगन, मेहनत के साथ–साथ दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में निर्भया की माता श्रीमती आशा देवी ने भी छात्राओं को सम्बोधित किया।अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा आयोजित छात्र–युवा संसद के दूसरे दिन आहुत छात्रा संसद में देशभर से आयी 300 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस छात्रा संसद में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषयों पर गहन चर्चा हुई। विभिन्न प्रदेशों से आयी छात्राओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ने तथा नई ऊंचाइयों को छूने के मार्गों पर विचार–विनिमय हुआ। इस छात्रा संसद में एक बृहत प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सौंपा जायेगा एवं उसके बिन्दुओं पर कार्यवाही की मांग की जायेगी। ■

"महिला हित में उठाया गया कोई भी कदम तभी कारगर हो पायेगा जब समस्त महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जायेगी। शिक्षा, मात्र साक्षरता नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा जिससे महिलायें अपने, समाज व राष्ट्र के विषय में निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। आज महिलाओं को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है, तभी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के साथ-साथ सम्पूर्ण मानवता का सर्वतोमुखी विकास सम्भव होगा। एक महिला के शिक्षित सुसंस्कारित होने से पूरा परिवार संस्कारित होता है। वह परिवार व समाज की नींव है। व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्ति के सर्वांग व्यक्तित्व का निर्माण करती है नारी। नारी का कार्य पारस पत्थर से भी बढ़कर है क्योंकि पारस मात्र लोहे को सोना बना सकता है लोहे को पारस नहीं बना सकता परन्तु स्त्री एक माँ, बहन,पुत्री व पत्नी के रूप में व्यक्ति तथा समाज का अपने से कहीं अधिक परिष्कार व संस्कार कर सकती है तथा करती भी है। इसीलिये स्त्री का शिक्षित होना समाज के लिये आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है।"

ममता यादव, अ.भा. छात्रा प्रमुख

संसद

अभाविप की सराहनीय पहल, एक मंच पर आये पूर्वोत्तर के छात्र नेता

पूर्वोत्तर के विकास का लिया संकल्प

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित पूर्वोत्तर छात्र युवा संसद के तीसरे दिन पूर्वोत्तर भारत से जुड़े मसलों पर मंथन हुआ। संसद के उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को हमें समृद्धि की क्षमता वाला क्षेत्र समझना चाहिए ना कि एक पिछड़ा क्षेत्र। पूर्वोत्तर में विकास की असीम संभावनाएं हैं और वर्तमान की केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दे रही है।

आपको बतादें कि एनडीएमसी सभागार में आयोजित पूर्वोत्तर छात्र संसद में पूर्वोत्तर भारत के सात प्रदेशों से 53 छात्र संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री सम्मिलित हुए। इनमें बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर के जनजातीय छात्र संगठनों के नेता रहे।

उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय युवा मामलें तथा खेल मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल साथ में अभाविप पदाधिकारी

श्री सोनेवाल ने केन्द्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए सरकार कई योजनाओं को संचालित कर रही हैं। पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। आज आवश्यकता है कि पूर्वोत्तर के युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगे, इस हेतु उन्हें उचित अवसर मिलने चाहिए और हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अभाविप द्वारा आयोजित इस संसद को संवाद का माध्यम बताया और इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में छात्रों के साथ समस्या हुई तब अभाविप समाधान खोजने की दिशा में आगे बढ़ा है। राष्ट्रविरोधी ताकतों के द्वारा छात्रों के बीच भय पैदा किये जाने की स्थिति में भी विद्यार्थी परिषद ने छात्रों की सहायता की है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर को कुदरत ने सबकुछ दिया है, लेकिन आज इसे आतंकवाद के लिए पहचाना जाता है। सरकार लगातार यहां माहौल को बेहतर बनाने में जुटी है और हमारी कोशिश है कि पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से मजबूती के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम जारी है और शैक्षणिक मोर्चे पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे है। पूर्वोत्तर का विकास सबके साथ ही संभव है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि पूर्वोत्तर के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की ओर से व्यापक स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक मोर्चे पर भी देशवासियों के बीच उत्तर–पूर्व राज्यों की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार स्कूली व विश्वविद्यालय स्तर पर प्रयास कर रही है और इसे किताबों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं बनेगा। हमारी सरकार अमल में विश्वास रखती है और अब जरूरत है कि अंतरराज्यीय व्यापार शुरू हो ताकि विकास में तेजी आए।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आम्बेकर ने उपस्थित छात्र नेताओं को पूर्वोत्तर के विकास का संकल्प लेकर जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस संसद का उद्देश्य सकारात्मक चर्चा से समस्याओं का समाधान खोजना है। अभाविप पूर्वोत्तर के युवाओं के साथ सदैव खड़ी है। अभाविप की मांग है कि पूर्वोत्तर भारत में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को पूर्वोत्तर में अच्छे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। श्री आम्बेकर ने कहा कि आने वाले समय में विश्व के साथ व्यापार में पूर्वोत्तर का बड़ा योगदान होगा। पूर्वोत्तर में मौलिक वस्तुएं अभी आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं, ऐसे में यह विविध गुण ही व्यापार की दिशा में प्रभावी सिद्ध होंगी।

इस पूर्वोत्तर छात्र नेता संसद में शिक्षा, विकास, सुरक्षा व अवसरों पर बृहत चर्चा हुई। इसके अलावा हिंसा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त एवं विकास युक्त उत्तर–पूर्व क्षेत्र कैसे बने इसको लेकर भी विचार हुआ। सत्रों में भारत सरकार के डोनर (DONER) मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय व गृह मंत्रालय के अधिकारियों से प्रश्नोत्तर व चर्चा द्वारा छात्र नेताओं ने पूर्वोत्तर के विषय में अपने सुझाव दिये। संसद में प्रतिभाग करने वाले संगठनों में बोडो, मिसिंग, खाती, जैनतिया, गारो, कोच, चकमा, मिजो, ओलो, नोक्टे, न्यीशी, कार्बी, दिमासा, कसारी, राभा, तिवा, मंचू, वांचो, थंसा, सागिन, मोग्का, आदी, छिग्फो सहित अन्य जनजातीय समुदायों के छात्र संगठनों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से थे। ■

देश को समृद्ध बनाने में युवाओं की भूमिका अहम

सोलापुर। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के विजन–2020 के आधार पर देश को प्रगति के पथ पर चलाने के लिए हम सभी को एकजुट प्रयास करने की जरूरत है। कलाम के विजन को मूर्त रूप देने और देश के विकास में हमारा सहयोग बढ़े इसके लिए हमें अपनी कल्पनाओं की उड़ान को और आगे बढ़ाते हुए कार्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता है। यह बातें एन. बी. नवले सिंहगड़ अभियांत्रिकी माहाविद्यालय के शिक्षक श्री विजय नवले ने तंत्रशिक्षण विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रांत स्तरीय कार्यशाला में कहीं। इस दौरान, उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि इंजीनियरों की भूमिका देश को समृद्ध बनाने की दिशा में होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान से देश की समृद्धि और बढ़ें। इतना ही नहीं उन्होंने राष्ट्र निर्माण में तंत्रज्ञ की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

वहीं, विज्ञान आश्रम के कार्यकारी निदेशक श्री योगेश कुलकर्णी ने 'सतत् प्रोद्योगिकी' विषय का विवरण करते हुए कहा कि शाश्वत तंत्र ज्ञान हमें पर्यावरण के चक्र से ही सिखने को मिलता है। ऐसे में प्रकृति की उपेक्षा हमारे विनाश का भी द्योतक होती है क्योंकि हम प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं की उपभोग तो करते हैं पर उसके संचय पर ध्यान नहीं देते। इसके अलावा, कार्यशाला में एन. बी. नवले सिंहगड़ अभियांत्रिकी माहाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. वरदराज बापट ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सत्र में अपनी विचारधारा, भारत की संस्कृति और देश समाज में भारतीय परिवेश आदि अलग–अलग बिंदुओं पर चर्चा की।

तंत्रशिक्षण विद्यार्थी परिषद द्वारा सतत अभियान्त्रिकी विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रांत स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन सोलापुर के प्रसिद्ध उद्योजक श्री वासुदेव बंग ने किया था। जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रांत अध्यक्ष डॉ. वरदराज बापट, कार्यशाला की प्रमुख प्रा. सरिता बलशेटवार, सोलापुर शहर के अध्यक्ष प्रा. डॉ. कांबले आदि लोग उपस्थित रहें। इस कार्यशाला में दस जिलों के 20 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ 56 की संख्या में प्राध्यापक और शिक्षक भी उपस्थित रहें।

विकसित भारत के स्वप्नद्रष्टा - डॉ. कलाम

✍ अवनीश राजपूत

भारत को विकसित देश के रूप में हर कोई देखना चाहता है लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हुए जिनके अंदर भारत को दिशा और दशा देने की प्रतिबद्धता दिखी। एपीजे अब्दुल कलाम भी उन्हीं लोगों में से एक थे। पंद्रह अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी गाँव के एक सामान्य परिवार में जन्में अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो आदमी अपने सामर्थ से शिखर तक पहुंच सकता है। अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और बुद्धिमता से ना सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की बल्कि भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफर भी तय किया। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना पूरे विज्ञान जगत के लिए सम्मान तथा प्रतिष्ठा की बात थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए दूसरे क्षेत्रों में भी सब कुछ आसान और सहज हो जाता है। डॉ. कलाम इस बात को चरितार्थ करते हैं। अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और लगन से भारत को वो शक्ति दी जिससे भारत अपनी धाक दुनिया के सामने जमा सका। कलाम के नेतृत्व में ही भारत ने नाग, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और अग्नि जैसे मिसाइल विकसित किए। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम को इसीलिये मिसाइल मैन भी कहा गया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की।

डॉ. कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम् कस्बे में एक मध्यमवर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। इनकी माँ, आशियम्मा उनके जीवन की आदर्श थीं। डॉ. कलाम की शिक्षा रामेश्वर के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई थी। वह अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बांटने का भी काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वह कुरान और भगवद् गीता दोनों का अध्ययन करते थे। इतने महत्तवपूर्ण व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना सरल नहीं है। डॉ. कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्ज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते थे। साहित्य में रूचि रखने वाले डॉक्टर कलाम, कविता लिखने के साथ–साथ वीणा भी बजाते थे और अध्यात्म से बहुत गहराई तक जुड़े रहे।

डॉ. कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला था। शायद यही कारण था कि अपनी लिखी पुस्तकों की रॉयल्टी का अधिकांश हिस्सा वह स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद में दे देते थे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार की राशियों को भी वह अक्सर परोपकार के कार्यों के लिए अलग से रखते थे। इतना ही नहीं जब–जब देश में प्राकृतिक आपदाएँ आई हैं, तब–तब डॉ. कलाम की मानवीयता एवं करुणा निखरकर सामने आई हैं। जब वे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में कार्यरत थे तो उन्होंने हर राष्ट्रीय आपदा में विभाग की ओर से बढ़ चढ़कर राहत कोष में मदद की। डॉ. कलाम का मानवतावाद मनुष्यों की समानता के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित था। 25 जुलाई, 2002 की शाम को भारत के राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद सँभालने के दिन घटित एक बात से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उस दिन राष्ट्रपति

भवन में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी जिसमें रामेश्वरम् मस्जिद के मौलवी, रामेश्वरम् मंदिर के पुजारी, सेंट जोसेफ कॉलेज के फॉदर रेक्टर सहित कई धर्मों एवं सगठनों के लोग वहां उपस्थित थे।

'अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मस्तिष्क वालों का देश बनाना है, तो मैं समझता हूं कि समाज के तीन लोग इसमें सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें पिता, माता और गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं।' – डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

डॉ. कलाम ने अपनी समस्त ऊर्जा को राष्ट्र–निर्माण की दिशा में लगाने के लिए दिसंबर 1999 में डी. आर. डी. ओ. को छोड़ने का फैसला किया, परंतु सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बाद उन्हें 'इंडिया मिलेनियम मिशन' नामक परियोजना में अपने विजन–2020 को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद दिया गया। वे 2001 तक इस पद पर रहे। इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया जिसका सभी ने स्वागत किया। 18 जुलाई, 2002 को संपन्न हुए चुनाव में डॉ. कलाम नब्बे प्रतिशत मतों के भारी बहुमत से भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। डॉ. कलाम ने "विंग्स आफ फायर", "इग्नाइटेड माइंड्स" जैसी कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावां उन्हें विभिन्न सम्मान और पुरस्कार मिले हैं जिनमें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सहित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का नेशनल डिजाइन अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉ. बिरेन रॉय स्पेस अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी आफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए जी. एम. मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शामिल हैं। डॉ. कलाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में आगंतुक प्रोफेसर भी रहे। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरूवनंतपुरम् में कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एयरो इंजीनियरिंग के प्रध्यापक के पद पर भी कार्यरत रहे। ऐसे युगपुरुष के बारे में जितना भी कुछ कहा जाय, वह कम ही है।

अब्दुल कलाम की कही पांच यादगार बातों पर एक नजर-

1. जिंदगी कठिन है। आप तभी जीत सकते हैं जब आप मनुष्य होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार के प्रति सजग हैं।

2. आसमान की ओर देखें। हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो सपना देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास कर रहा है।

3. हमें दुनिया तभी याद रखेगी जब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और विकसित भारत देंगे जो कि आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक विरासत से मिला हो।

4. जो अपने दिल से काम नहीं करते जिंदगी में भले ही कुछ पा लें, लेकिन वह खोखली होती है। यह आपके मन में कड़वाहट भरती है।

5. शिक्षाविदों को छात्रों का रोल मॉडल बनना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि उनमें खोजने, जांचने, सृजनात्मकता और उद्यमशीलता की क्षमता उभरे। ■

विश्व हिन्दी सम्मेलन

हिन्दी दिवस के बहाने

✍ डॉ. राजनारायण शुक्ल

बहुत विचार विमर्श के बाद भारत की संविधान सभा ने हिन्दी को 'राजभाषा' का दर्जा दे दिया। महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी, गोपाल स्वामी अय्यंगा जैसे अनेक महा–मना नेताओं के अत्यन्त आग्रह पर यह माना गया कि सम्पूर्ण देश के बीच परस्पर संवाद की कोई एक भाषा अगर चुननी है तो वह हिन्दी ही हो सकती है। गुजराती के महान साहित्यकार नर्मद ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वप्रथम उद्घोष् किया था। इसके बाद ही यह निर्णय हुआ कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा होगी। वहीं, संविधान सभा में ऐसे महानुभव भी थे, जो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित थे और हिन्दी को पिछड़ी भाषा मानते थे। परन्तु उन्होंने हिन्दी को पीछे रखने का एक ज्यादा हानिकारक विचार आगे यह रखा कि हिन्दी को लाने से तमाम क्षेत्रीय भाषा के लोगों को चोट पहुँच सकती है जबकि यह पहले से ही स्पष्ट था कि हिन्दी की वकालत करने वाले अधिकांश महानुभाव गैर हिन्दीभाषी थी। फलतरू एक शर्त लगा दी गई कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय कार्यों के लिए जारी रहेगा।

'राजभाषा' का अर्थ ही यह होता है कि वह उस देश की सरकारी व राजकाज की अर्थात शासकीय कार्यों की भाषा होगी, लेकिन तुरन्त ही यह कहा गया कि अंग्रेजी अगले 15 वर्षों तक चलती रहेगी। यानि हिन्दी को राजभाषा के सिंहासन पर बिठाया गया पर उसके हाथों–पैरों में बेड़ियां डालकर, कितनी विचित्र बात हुई। और जैसा कि संभावित था, 15 वर्ष बीते और भी कितने 15 वर्ष हो गये, अंग्रेजी चल रही है। न्यायपालिका में भी, शासन के तमाम अंगों में, प्रशासकीय कार्यो में। जबकि हिन्दी को सांत्वना स्वरूप एक दिन का अधिकार दिया गया यानि 14 सिंतबर, हिन्दी दिवस।

हां, उस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान ने संघ सरकार पर यह दायित्व डाला कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ायेगी। उसका विकास करने की व्यवस्था बनाएगी ताकि वह भारत को समग्र सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके।

शासकीय कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण किया गया। प्रशासनिक अनुवाद के लिए प्रत्येक विभाग में अनुवादकर्मी रखे गये हैं। मगर बिडंबना यह है कि जो भी अनुवाद सरकारी स्तर पर हो रहा है या जो भी प्रशासनिक शब्दावली बन रही है, उसके कारण उसके द्वारा जो भी पत्र–व्यवहार सामने आ रहा है उससे हिन्दी के प्रचार–प्रसार में गति आने की जगह हिन्दी की अधोगति हो रही है। इतने कठिन और पूरी तरह ना समझ आने वाले शब्दों का निर्माण हो रहा है। जिससे अन्ततः व्यक्ति को लगता है कि इस हिन्दी से तो अंग्रेजी ही ठीक है। सम्भवतः ऐसे स्थानों पर बैठे अधिकारियों की यही मंशा हो। 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन भोपाल में तो एक हिन्दी विद्वान ने यहां तक कहा कि मैं ऐसे कुछ प्रशासनिक तन्त्र के द्वारा तैयार और अनुदित शब्द बोल रहा हूँ जिसे यहाँ बैठा कोई हिन्दी विद्वान समझा दें तो वह उसे पचास हजार रुपये का पुरस्कार देगें।

हिन्दी भाषा के लिए सरकारी मशीनरी की इसी जड़ता के बीच पिछले प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में वक्तव्य देकर ना केवल भारत को बल्कि सारे विश्व को चौंका दिया। देश में हिन्दी की स्थिति को लेकर फिर से गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। सम्भवतः संयुक्त राष्ट्र संघ को पहली बार लगा होगा कि भारत की भाषा अंग्रेजी

नहीं हिंदी है। हिन्दी अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बन पाई है। जबकि अत्यन्त छोटे देशों की भाषाएं ये दर्जा बहुत पहले प्राप्त कर चुकी हैं। दोबारा से यह स्थिति तब दिखाई दे रही है जब नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लगातार विदेशों में हिंदी बोलने का क्रम बनाए रखा जबकि नरेन्द्र मोदी स्वयं गैर हिन्दी भाषी हैं।

भारत सरकार विश्व में हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलन कराती है। हालांकि अभी तक ये सम्मेलन औपचारिक रूप से हिन्दी के लिए कुछ करते–दिखने के लिए ही अधिक हुए हैं। पर पहली बार 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन, भोपाल में इस पर गम्भीर रूख अपनाया गया। मैं 9वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का भी साक्षी रहा जो कि केवल एक औपचारिक निर्वाह था। जबकि भोपाल के समानान्तर सत्रों की अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के मन्त्री स्वयं कर रहे थे और उनके साथ संबंधित अधिकारी भी थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सम्मेलन में हिन्दी विद्वानों के जो भी सुझाव आ रहे हैं उनकी रिर्पोट बनाकर रखी जायेगी और उन्हें अक्षरशः लागू किया जायेगा। स्वयं विदेश मन्त्री ने घोषणा की कि दुनियाभर में जहाँ भी उनसे हिन्दी में बात की जायेगी वह उसका जबाव अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में ही देंगे।

10वें हिन्दी सम्मेलन, भोपाल के एक सत्र में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने हैरानी से हमारे दूतावास के अधिकारियों से प्रश्न किया कि आप लोग विदेश में भारतीयों से व विदेशी, हिन्दी भाषियों से भी अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं ? प्रशासनिक शब्दावली का सुझाव भी आया कि हिन्दी भाषा में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शब्द लेने चाहिए, जिससे ना केवल हिन्दी का शब्द भंडार समृद्ध होगा बल्कि क्षेत्रीय भाषा–भाषी लोगों का लगाव हिन्दी से और ज्यादा बढ़ेगा। कल्पना कीजिए कि तमिल, तेलगू, मराठी, बांगला आदि सभी भाषाओं के हजारों दैनिक बोलचाल के साथ हिन्दी में बोले जा रहे हैं तो सभी की हिन्दी में कितना अपनापन दिखेगा। यह भी सुझाव वहां आया कि प्रशासनिक शब्दावली में अनुवाद की दुरूह भाषा की जगह क्षेत्रीय भाषा के शब्दों को अधिकाधिक जगह दी जाए। जिसके लिए जो समिति बने वह हिन्दी–अंग्रेजी जानने वाले राजभाषा अधिकारियों की नहीं बहुभाषा–भाषी विद्वानों को लाकर इनके द्वारा क्षेत्रीय शब्द भंडार से हिन्दी को समृद्ध किया जाए व प्रशासनिक पत्र–व्यवहार बोलचाल की हिन्दी में हो। हिन्दी को राजभाषा तय करते समय शर्तों में कहा गया था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में चलाया जा सकेगा, जबकि इसके उलट व्यवहार हो रहा है। संविधान की भावना की उपेक्षा हो रही है। किसी भी देश की बड़े नीति–निर्णयों की पहली प्रति हिन्दी में आनी चाहिए व उसका अनुवाद आवश्यक हो तो अंग्रेजी में हो जब कि इसके उलट हो रहा है। यहाँ सारे निर्णय व आदेश अंग्रेजी में छापे जाते हैं और जरूरत के आधार पर हिन्दी अनुवाद किया जाता है।

भाषा, संस्कृति देश की पहचान से जुड़ी होती है। हमें विश्व में अपनी पहचान के लिए अंग्रेजी नहीं भारतीय भाषा की ही आवश्यकता है, जो कि सर्वमान्य रूप से हिन्दी हो सकती है। अतः जितना शीघ्र सम्भव हो इस तथ्य को अंगीकृत कर हमें इसका पालन करना चाहिए।

(लेखक हिन्दी विभाग, एस.अडी. कॉलेज, गाजियाबाद से संबंद्ध हैं)

■

गांधी जयंती पर विशेष

विद्यार्थियों के प्रति गांधी जी के विचार

✍ संजीव कुमार सिन्हा

महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में अधिक ख्यात हैं। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन और असहयोग को अस्त्र बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दीं। इस आंदोलन में उन्होंने करोड़ों भारतीयों का सहभाग सुनिश्चित करते हुए अंततः औपनिवेशवाद को उखाड़ फेंका। गांधीजी अद्‌भुत आंदोलकारी तो थे ही साथ ही वे विचारक भी थे। जीवन के अधिकांश पहलूओं के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। सत्य, अहिंसा, धर्म, सभ्यता, नारी, शिक्षा, अस्पृश्यता, ग्राम स्वराज, स्वदेशी, खादी, आरोग्य, स्वच्छता जैसे विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने समय–समय पर विचार रखे थे। इसी तरह उन्होंने समाज के महत्त्वपूर्ण घटक 'विद्यार्थी' पर खूब चिंतन–मनन किया था और इस संबंध में अपनी पत्रिका, 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' में अनेक संपादकीय टिप्पणियां और लेख लिखे।

गांधी मानते थे विद्यार्थी औपनिवेशिक शासन में अपने देश से घृणा करना सीखते हैं। उन्हें विश्वास था कि "हमारे स्कूल और कॉलेज हमें बहादुर बनाने के बजाय खुशामदी, डरपोक, अनिश्चयी और अस्थिर बनाते हैं।"(हरिजन, 17–08–1947)

गांधीजी ने विद्यार्थियों को लेकर चरित्र–निर्माण, ब्रह्मचर्य, काम–विज्ञान की शिक्षा, दलगत राजनीति, नशामुक्ति और रचनात्मक कार्य जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बात कही थी।

चरित्र की आवश्यकता

गांधीजी ने सर्वाधिक जोर छात्रों के चरित्र–निर्माण पर दिया था। वे मानते थे कि समस्त ज्ञान का उद्‌देश्य चरित्र–निर्माण होना चाहिए। गांधीजी अंग्रेजी शिक्षा पर विश्वास नहीं करते थे और कहते थे कि यह शिक्षा चरित्र का निर्माण नहीं करती। उन्होंने लिखा, "आपका सारा पांडित्य, आपका शेक्सपियर और वर्ड्‌स्वर्थ का तमाम अध्ययन व्यर्थ होगा, यदि साथ–साथ आप अपना चरित्र–निर्माण नहीं करेंगे और अपने विकारों और कार्यों पर प्रभुत्व प्राप्त नहीं करेंगे। जब आप अपने पर काबू पा लेंगे और अपने को वश में रखना सीख जाएंगे, तब आप निराशा के स्वर नहीं निकालेंगे।" (यंग इंडिया, 19–09–1929)

"विद्यार्थी जीवन की उपमा संन्यासी जीवन से ठीक ही दी गई है। उसे सादा जीवन और उच्च विचारों की मूर्ति बनना ही चाहिए। उसे अनुशासन का अवतार होना चाहिए। उसे अपने अध्ययन से ही सुख मिलना चाहिए।" (हरिजन, 17–08–1947)

ब्रह्मचर्य

भारतीय परंपरा के अनुसार, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्त्व है। इसका अर्थ होता है–मन, वचन और कर्म की पवित्रता। गांधीजी इसे महत्त्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने लिखा था, "हिंदू धर्म के अनुसार, विद्यार्थी ब्रह्मचारी होता है और विद्यार्थी–अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम होती है। अविवाहित अवस्था ब्रह्मचार्य का संकुचित अर्थ है। मूल अर्थ विद्यार्थी जीवन या अवस्था है। इसका अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण।" (हरिजन, 21–11–1936)

काम–विज्ञान की शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में 'काम विज्ञान की शिक्षा' को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसे लेकर महात्मा गांधी के विचार संयमित हैं। काम–विज्ञान की शिक्षा का हमारी शिक्षा–प्रणाली में क्या स्थान है? इस संबंध में वे राय व्यक्त करते हैं, "काम–विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वह जो काम विकार को काबू में रखने या जीतने के काम आता है और दूसरा वह जो उसे उत्तेजन और पोषण देने के काम आता है। पहले प्रकार के विज्ञान की शिक्षा बाल शिक्षा का उतना ही आवश्यक अंग है, जितनी दूसरे प्रकार की हानिकारक और खतरनाक है, और इसलिए उससे बचना ही उचित है।.....

"जिस काम–शिक्षा के पक्ष में हूं, उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि इस विकार पर विजय प्राप्त की जाय

और उसका सदुपयोग हो।'' (हरिजन, 21–11–1936)

नशामुक्ति

गांधीजी मानते थे कि एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए नशामुक्ति सबसे पहली जरूरत है। उन्होंने जो सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था मद्यनिषेध उसका एक मुख्य अंग था। उन्होंने विद्यार्थियों से भी शराब, सिगरेट आदि व्यसनों से दूर रहने का आग्रह किया था।

रचनात्मक कार्य

गांधीजी ने विद्यार्थियों से रचनात्मक कार्य करने का भी आह्वान किया था। उन्होंने कताई और खादी, ग्रामसेवा, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू–मुस्लिम एकता, समाज सुधार आदि मुद्दों पर विद्यार्थियों से सक्रियता से जुट जाने का आह्वान किया। वे कहते थे कि विद्यार्थियों को साथ लेकर हरिजन–मुहल्लों में जाओ और अपने साथियों सहित उन मुहल्लों को साफ करो, उनके बच्चों से दोस्ती करो और उन्हें सफाई, स्वास्थ्य विज्ञान आदि की उपयोगी शिक्षा दो।

विद्यार्थी आंदोलन

'छात्र राजनीति' के मुद्दे पर महात्मा गांधी का स्पष्ट विचार था कि छात्रों को दलगत राजनीति से मुक्त रहना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब 1921 में महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से कहा, 'स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करो' तो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक का बहिष्कार किया था। गांधीजी का मानना था कि छात्र संगठन राजनीतिक दल के साथ न जुड़े। 26 जनवरी 1941 को अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के प्रधानमंत्री के नाम से लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा, ''विद्यार्थियों का दलगत राजनीति में पड़ने से काम नहीं चल सकता। जैसे वे सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे सब दलों की बात सुन सकते हैं। परंतु उनका काम यह है कि सबकी सच्चाई को हजम करें और बाकी को फेंक दें। यही एकमात्र उचित रवैया है, जिसे वे अपना सकते हैं। सत्ता की राजनीति विद्यार्थी–संसार के लिए अपरिचित होनी चाहिए। वे ज्यों ही इस तरह के काम में पड़ेंगे, त्यों ही वे विद्यार्थी के पद से च्युत हो जाएंगे और इसलिए देश के संकटकाल में उसकी सेवा करने में असफल होंगे।''

गांधीजी का मानना था कि विद्यार्थियों का एक संगठन होना चाहिए। वे कहते हैं, ''इसमें संदेह नहीं है कि हिंदू, मुसलमान और अन्य सब विद्यार्थियों का मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। विद्यार्थियों को क्रियात्मक राजनीति से अलग रहना ही चाहिए। यह देश के इकतरफा विकास की निशानी है कि सब दलों ने विद्यार्थी–जगत् का अपने–अपने मतलब से उपयोग किया है। (हरिजन, 17–08–1947)

देश का अग्रणी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भी दलगत राजनीति से मुक्त रहकर शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय है। 'छात्र राजनीति' के मुद्दे पर महात्मा गांधी लिखते हैं, ''1920–21 में विद्यार्थियों को स्कूल–कॉलेजों से निकालने और उन्हें राजनीतिक कार्य हाथ में लेने और जेल की जोखिम उठाने की प्रेरणा देने में मेरा कम हाथ नहीं था। मेरे ख्याल से अपने देश के राजनैतिक आंदोलन में प्रमुख भाग लेना उनका स्पष्ट कर्तव्य है। दुनिया भर में वे ऐसा कर रहे हैं। भारत में, जहां पिछले दिनों तक राजनैतिक जाग्रति दुर्भाग्यवश ज्यादातर अंग्रेजी शिक्षित वर्ग तक सीमित रही है, उनका कर्तव्य वास्तव में और भी बड़ा है। चीन और मिस्र में राष्ट्रीय आंदोलन को संभव ही विद्यार्थियों ने बनाया। (यंग इंडिया, 29–03–1928)

'विद्यार्थियों के प्रति' महात्मा गांधी के विचार को समग्रता में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वे ऐसा विद्यार्थी चाहते हैं जो स्वाध्यायी हो, नैतिकवान हो, ब्रह्मचारी हो, भारतीय भाषा का अनुरागी हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूक ही नहीं अपितु उसमें सहभागी हो परंतु दलगत राजनीति से मुक्त हो और रचनात्मक कार्य में सहभागी हो। गांधीजी ने जब देश परतंत्र था तब ये विचार व्यक्त किए थे, परंतु महापुरूष के विचार प्रकाशस्तंभ होते हैं और विद्यार्थियों के लिए उनके विचार निश्चित रूप से आज भी पाथेय हैं। ■

छोटे कद का दूरदर्शी फैसला, पलट दिया दुश्मन का मंसूबा

✍ दीपक बरनवाल

देश इन दिनों 1965 की लड़ाई की स्वर्ण जयंती मना रहा है। मौका खास है तो जश्न तो बनता ही है। यह ऐसा यादगार युद्ध है जब पहली बार भारत ने सीमा लांघकर दुश्मन के घर में घुसकर सबक सिखाने का कदम उठाया। इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, वह भी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। 1965 की लड़ाई का अंत भले ही ताश्कंद समझौते के रूप में हुआ लेकिन रक्षा जानकार बताते हैं कि संघर्षविराम लागू होने के समय भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा था। यह और बात है कि पाकिस्तान इस लड़ाई को अपनी जीत के रूप में दुष्प्रचारित करता रहता है। सच यह भी है कि लड़ाई में किस पक्ष की जीत हुई, वह इस बात पर निर्भर करता है कि किसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? पाकिस्तान का मंसूबा कश्मीर को भारत से छीनने का था और उसे अपने इस मंसूबे में कामयाबी नहीं मिली। उसका सबसे बड़ा कारण था उस समय का नेतृत्व, छोटे कद का एक सशक्त व्यक्ति जिसने अपने फैसले से विरोधियों को पस्त कर दिया था। पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा, 'युद्ध का सबसे बड़ा फैसला (लाहौर की तरफ बढ़ना), सबसे छोटे कद के शख्स ने लिया।'

पाकिस्तान के हुक्मरानों को गलतफहमी थी कि 1962 की लड़ाई में चीन से मिली हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल काफी गिरा हुआ है। भारतीय सेना को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई ही थी कि 1964 में देश के पहले व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की मौत हो गई। नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान एक कमजोर नेतृत्व मानता था। उसकी ठोस वजह भी थी। तब के समय खुद कांग्रेस पार्टी भी उन्हें अस्थायी व्यवस्था के रूप में ले रही थी। हालांकि 1965 युद्ध के बाद उनकी छवि बेहतर हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा को लगा कि भारतीय सेना के गिरे हुए मनोबल, कूटनीतिक और सामरिक नजरिए से कमजोर हुए भारत पर हमला बोलने और कश्मीर हड़पने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। उन्हें लगा कि अगर इस बार कश्मीर पर कब्जा नहीं हो पाया तो शायद ही फिर कभी इसे हासिल कर पाएंगे।

पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शंकर बाजपेई के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को लगने लगा कि हिंदुस्तान कमजोर है। एक तो यह देश लड़ना नहीं जानता और दूसरा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व बहुत कमजोर है। वह दिल्ली आने वाले थे लेकिन नेहरू के निधन के बाद उन्होंने यह कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी कि अब वहां किससे बात करेंगे। यात्रा रद्द की सूचना पर शास्त्रीजी ने कहा था, कोई बात नहीं, आप मत आइए हम आ जाएंगे। वो काहिरा गए हुए थे, लौटते वक्त शास्त्रीजी एक दिन के लिए कराची रूके। उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ने राष्ट्रपति अयूब खान आए थे। उन्होंने अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा था कि इस व्यक्ति यानि शास्त्री से बात करने में तो कोई फायदा नहीं है। उस वक्त शंकर बाजपेई स्वयं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उपस्थित थे।

रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना 1965 की लड़ाई के समय तकनीक और हथियारों के मामले में भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति में थी। उसके पास बड़ी संख्या में अमेरिकी पैटन टैंक थे जबकि भारत के पास द्वितीय विश्व युद्ध के टैंकों का दस्ता था। यह युद्ध टैंकों की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंकों की यह सबसे भीषण लड़ाई थी। पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। इस लड़ाई ने साबित कर दिया

कि केवल तकनीक और अच्छे हथियार के बलबूते आप युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध जीतने के लिए अच्छा नेतृत्व, बेहतर तालमेल और भावनात्मक ऊर्जा की भी जरूरत होती है जो ऐन मौके पर पाकिस्तानी सेना और उसके हुक्मरानों के पास नहीं थी। 1965 का भारत–पाकिस्तान युद्ध ने भारत को अपनी रणनीतिक और सामरिक तैयारी को और पुख्ता बनाने के लिए प्रेरित किया।

कैसे हुई युद्ध की शुरुआत

एक सितम्बर 1965 को तड़के साढ़े तीन बजे कश्मीर के छंब सेक्टर में पाकिस्तान ने टेकों व तोपों से हमला कर दिया। इससे भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां भौचक रह गई। सुबह नौ बजते–बजते छंब पाकिस्तान के कब्जे में था। संयोग था कि एक दिन पहले ही कश्मीर के हालात का जायजा लेने थल सेनाध्यक्ष जनरल जे. एन. चौधरी कश्मीर गए थे। वो उस दिन दिल्ली लौटने वाले थे। पाकिस्तानी हमले की सूचना के बाद केंद्र सरकार सकते में आ गई। आनन–फानन में तत्कालीन रक्षामंत्री यशवंत राव चव्हाण ने बैठक बुलाई, जिसमें राजधानी दिल्ली रक्षा मंत्रालय के कार्यालय कमरा संख्या 108, साउथ ब्लॉक में दोपहर चार बजे आकस्मिक बैठक तत्कालीन रक्षा मंत्री एयर मार्शल अर्जन सिंह, रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव एचसी सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार मंगलम के साथ गहन मंत्रणा हुई।

बैठक शुरू हुए आधा घंटा बीता भी नहीं कि थल सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी पहुंचे। उन्होंने एयर मार्शल अर्जन सिंह के साथ कुछ देर दबे शब्दों में बात की और रक्षा मंत्री चव्हाण की तरफ देखकर कहा कि उन्हें छंब सेक्टर में वायु सेना के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। चौधरी ने चव्हाण से ये भी कहा कि उन्हें जवाबी हमला करने के लिए सीमा पार करने की अनुमति भी मिले। चव्हाण कुछ मिनट तक सोचते रहे, कमरे में मौजूद सबकी निगाहें उन पर थीं। फिर उन्होंने मुलायम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, 'भारत सरकार आपको छंब में वायु सेना के इस्तेमाल की अनुमति देती है। आप सीमा पर भारतीय सैनिकों के लिए भी सिग्नल जारी करें।' रक्षा सचिव पीवीआर राव ने चव्हाण के मौखिक आदेश को रिकॉर्ड किया। पांच बजकर 19 मिनट पर भारत के वैंपायर विमानों ने छंब पर बमबारी करने के लिए टेक ऑफ किया और इस तरह से 1965 का भारत–पाक युद्ध की शुरुआत हुई।

पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का निर्णय

वर्तमान समय में दस जनपथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय है जो कभी देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय हुआ करता था। एक सितम्बर 1965 को रात 11 बजकर 45 मिनट पर प्रधानमंत्री अचानक अपनी कुर्सी से उठे और दफ्तर के कमरे के एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से चहलकदमी करने लगे। शास्त्री के सचिव सीपी श्रीवास्तव ने बाद में अपनी किताब 'ए लाइफ आफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स' में लिखा, 'शास्त्री ऐसा तभी करते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था।' उन्होंने पुस्तक में लिखा कि उन्होंने शास्त्री जी को बुदबुदाते हुए सुना '... अब तो कुछ करना ही होगा।' आधी रात के बाद शास्त्री दफ्तर के बगल में बने निवास पर कुछ घंटे सोने के लिए चले गए। उस समय उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि प्रधानमंत्री ने तय किया था कि कश्मीर पर हमले के जवाब में भारतीय सेना लाहौर की तरफ मार्च करेगी। दो सितम्बर और तीन सितम्बर को उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और पाकिस्तान पर हमला करने की योजना को अंतिम रूप दिया।

कश्मीर में पाकिस्तानी सेना को हावी होते देख प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर पाकिस्तान पर आक्रमण की अनुमति दे दी। 6 सितम्बर, 1965 को भारतीय सेना अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर लाहौर की ओर बढ़

चलीं। लड़ाई जारी रखने की झिझक बाइस दिनों तक चलने वाली इस लड़ाई में भारत के करीब 3,000 और पाकिस्तान के करीब 3,800 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया जबकि पाकिस्तान ने भारत 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया। 1965 के युद्ध में भारत के 32 टैंक नष्ट हुए जबकि पाकिस्तान के अमरीका से मंगाए हुए अत्याधुनिक 97 पैटन टैंक नष्ट हुए और 28 टैंक भारत ने अपने कब्जे में ले लिए। पाकिस्तान अपनी तबाही देख घबरा उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान इस तबाही से हिल गए और उन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाने में ही भलाई समझी। अयूब इस युद्ध से इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा, 'मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी नहीं खतरे में डालेगा ...कभी नहीं।'

'कच्छ टू ताश्कंद' पुस्तक में फारूख बाजवा ने लिखा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने ढंग से काम किया लेकिन विदेश मंत्रालय उस तरह से काम नहीं कर पाई। तभी तो लड़ाई के दौरान दुनिया के बहुत कम देश खुलेआम भारत के समर्थन में उतरे। लड़ाई के अंतिम चरण पर युद्ध विराम करने का दबाव बन रहा था तो प्रधानमंत्री शास्त्री ने सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी से पूछा, 'अगर लड़ाई को कुछ दिनों तक और जारी रखा जाए तो क्या भारत की जीत हो सकती है।' बाजवा लिखते हैं यहां थलसेनाध्यक्ष से सूचना देने में चूक हुई थी। जनरल ने जवाब दिया कि भारत के सभी मुख्य हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं और बहुत से टैंक भी बर्बाद हो गए। लेकिन वास्तव में 22 सितंबर तक भारत ने सिर्फ 14 फीसद असलहे का इस्तेमाल किया था। उसके बाद युद्धविराम के लिए भारत तैयार हुआ। इस तरह से 22 सितम्बर, 1965 को दोनों ओर से बंदूकें शांत हो गईं। 11 जनवरी 1966 को ताश्कंद घोषणा के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की रात को ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मौत कैसे हुई, उस पर पर्दा आज तक उठ नहीं पाया।

इस युद्ध के बाद भारत ने कई महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कारगिल, हाजीपीर दर्रा, बजरंग गढ़ी, कलेरवन्द, रसूल पुर, चरवा, महाराजके, फिल्लोरा, डेराबाबा नानक, डोगराई और बारकी पर भारत का कब्जा हो गया। वहीं, छम्ब, फिजल्का, सुलैमान और खेमकरन भारत के हाथ से निकल गए। इस युद्ध से पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला। ■

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का अक्तूबर 2015 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों तथा खबरों का संकलन किया गया है। आशा है यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई–मेल पर अवश्य भेजें।

"छात्रशक्ति भवन,"
26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली – 110002
फोन : 011–23216298
ई–मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
वेबसाईट : www.abvp.org

पर्युषण पर्व के दौरान मीट बैन पर समीक्षा

✍ उत्कर्ष श्रीवास्तव

पर्युषण पर्व जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। श्वेतांबर इस पर्व को आठ दिन और दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी इसे दस दिनों तक मनाते हैं। इस पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी विभिन्न आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और योग–समाधि जैसी साधना जप–तप के साथ करके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। सब मिलाकर मानव की सोई हुई अन्तः चेतना को जागृत करने, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार, सामाजिक सद्भावना एवं सर्वधर्म समभाव के कथन को बल प्रदान करने के लिए पर्युषण पर्व मनाया जाता है।

देशभर में पर्युषण पर्व के दौरान मांस बिक्री पर लगी रोक का भारी विरोध हुआ और अधिकारों की दुहाई देकर लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे। सात साल पहले उच्चतम न्यायालय ने भी यह बात मानी कि मांस बिक्री पर कुछ दिन की रोक से मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, और भारतवर्ष में किसी समुदाय की भावनाओं का ख्याल करके ऐसी रोक को अतार्किक नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश एच. के. सेमा और मार्कण्डेय काटजू की पीठ ने वर्ष 2008 में दिये गये फैसले में भारतीय समाज की विविधता का वर्णन करते हुए मुगल सम्राट अकबर और अध के नवाब वाजिद अली शाह की सहिष्णुता का उदाहरण दिया था। पीठ ने कहा था कि ये उदाहरण देश में लगातार बढ़ रही असहिष्णुता की प्रवृत्ति के लिए है। बहुविविधता वाले हमारे देश में किसी समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़े समय के लिए लगे प्रतिबन्ध पर किसी को जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना और ना ही बुरा मानना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए चाहे वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना हों।

पर्युषण पर्व के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने 10 से 17 सितम्बर को मांस की बिक्री पर रोक और बूचड़खानों को बन्द रखने का आदेश दिया। वहीं, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने 13 व 18 सितम्बर को मांस पर प्रतिबन्ध का आदेश दिया। महाराष्ट्र में लगे प्रतिबन्ध के बाद राजस्थान, अहमदाबाद और जालंधर में भी जैन पर्व के दौरान मांस बिक्री पर पाबंदी लगा दी गयी थी। राजस्थान सरकार ने जहाँ 17, 18 और 27 सितम्बर को मांस बिक्री पर पाबन्दी लगायी, वहीं अहमदाबाद में पर्युषण पर्व पर नगर आयुक्त ने 10 से 17 सितम्बर तक एक सप्ताह की अवधि के दौरान गायों और बकरियों जैसे पशुओं के वध पर रोक लगाने का आदेश दिया। पंजाब के शहर जालंधर में 18 सितम्बर को मीट, अण्डों की सभी दुकानें, रेहड़ियाँ और बूचड़खानों को बन्द रखने का आदेश जारी किया गया।

भाजपा ने जहाँ प्रतिबन्ध का बचाव किया है, वहीं शिवसेना के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और एनसीपी ने प्रतिबन्ध का एक सुर में विरोध किया। शिवसेना समर्थकों व मनसे के कार्यकर्ताओं ने मांस बिक्री प्रतिबन्ध को निजी स्वतंत्रता की दखल बताकर अनैतिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। नैतिकता की हदें पार करते हुए विरोधियों ने जैन समुदाय के लोगों की दुकानों पर अण्डों की वर्षा की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो दुकानों के सामने मुर्गे और मुर्गियों का नाच करवाया। वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में मनसे ने जैन हाउसिंह सोसायटी के बाहर नॉनवेज फूड स्टॉल लगाकर मांस बेचा और खुलेआम मुर्गे का मांस भी खाया।

मटन व्यापारियों ने मांस बिक्री पर प्रतिबन्ध के खिलाफ बाम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर स्टे ऑर्डर जारी कर मीट की बिक्री पर लगा प्रतिबन्ध हटाने का आदेश दिया। जबकि पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख पर्वों व प्रमुख अवसरों जैसे–

रामनवमी, महावीर जयन्ती, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयन्ती और पुण्यतिथि आदि दिनों पर बूचड़खानों की बन्दी को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा था कि कुछ दिन के प्रतिबन्ध से व्यवसाय की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि मांसाहारी लोग भी कुछ दिन के लिए शाकाहारी हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी जमात व अन्य के बारे में दिये गये अपने इस फैसले के पैराग्राफ–67 में कहा था कि भारत के हर नागरिक और राज्य के जीवित प्राणी के प्रति सहृदय होना चाहिए। उसके प्रति दया की भावनी होनी चाहिए। जीवित प्राणियों के प्रति सहृदयता की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद–51ए.जी. में दी गयी है, जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। ये भारत वर्ष महात्मा गांधी, विनोवा भावे, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक की भूमि है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी धर्म या पवित्र ग्रंथ क्रूरता का पाठ नहीं पढ़ातें और ना ही क्रूरता को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय समाज बहुलका का समाज है। यहाँ अनेकता में एकता है, सभी एकसुर में कहते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के प्रति क्रूरता समाप्त होनी चाहिए। इस बहुधर्मी और विविधता से भरे हुए देश में वर्षों रहकर भी क्या हम इतने असहिष्णु हो चुके हैं कि महज कुछ दिने के लिए हम मांस बेचते या खाने से अपने आपको रोक नहीं सकते हैं? जबकि सबको मालूम है कि जो महत्व नवरात्रि का हिन्दुओं में, मुस्लिमों का रमजान में, सिखों का गुरु पर्व में और बौद्धों का बुद्ध पूर्णिमा में है वही महत्व पर्युषण पर्व का जैनियों में है।

■

कश्मीर में गोमांस पर प्रतिबंध कितना जायज....

जम्मू–कश्मीर में गोमांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लग गया है। उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गोमांस की बिक्री पर राज्य में रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर एवं जनकराज कोखाल की जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह निर्देश दिये हैं कि गोमांस पर रोक के आदेश का कड़ाई से पालन हो और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कहीं भी गोमांस की बिक्री ना हो।

परन्तु जम्मू कश्मीर में गोकसी पर कानूनन रोक लगाने के बाद सियासी भूचाल आ गया है। विभिन्नता के इस देश में लोग धर्म और रोजगार का हवाला देकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब गोकसी पर प्रतिबन्ध मुद्दा बना हो। इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दस वर्ष पहले 26 अक्तूबर 2005 को अपने फैसले में गोकसी पर रोक को सही ठहराया था। उस फैसले में गोकसी पर रोक लगाने वाले गुजरात के कानून को सही ठहराया गया था और गोमांस व भैसे के मांस को भोजन का महत्वपूर्ण जरिया मानने की दलील खारिज कर दी गयी थी। न्यायालय ने कहा था कि भारत में अब भोजन की कमी नहीं है और ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन उपलब्ध है, समस्या सिर्फ उसके सही वितरण की है।

जम्मू–काश्मीर विधान सभा में बीफ बैन पर मचे बवाल के बीच उच्चतम न्यायालय ने जम्मू–काश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले को निस्तारण के लिए तीन जजों की बेंच गठित करने के निर्देश दिये। उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा गोमांस की बिक्री पर लगाए प्रतिबंध को तीन महीने के लिए लागू नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि जम्मू–काश्मीर उच्च न्यायालय ने 8 सितम्बर 2015 को गोमांस की बिक्री पर बैन लगाया था। आरपीसी की धारा–298 ए के मुताबिक गाय, बैल या भैंस की इरादतन हत्या या वध दण्डनीय और गैर जमानती अपराध है, जिसके तहत 10 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

राजनीतिक एवं कूटनीतिक तरीके से हो नेपाल में चल रही समस्या का निस्तारण

प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद ने नेपाल की वर्तमान राजनीतिक समस्या को गम्भीरता से लेते हुए भारत–नेपाल सम्बंधों पर चिंता व्यक्त की है। एक लम्बे संघर्ष के बाद नेपाल में संविधान लागू होने का संक्रमण काल समाप्त हुआ है और एक हितकारी फैसला सामने आया है, जिसका सभी को हृदय से स्वागत करना चाहिए। यह ऐतिहासिक और शानदार उपलब्धि है।

जब संविधान तैयार किया जा रहा था तो बहुत से क्षेत्रों से लोगों और अनेक संगठन अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन किये। उनमें से कुछ आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के द्वारा उनकी सभी मांगों को नहीं मनवाया जा सकता, या फिर माँगों पर सहमति भी नहीं बन सकती है। मधेशी के बहुत से हिस्सों में एक साथ कई जगह प्रदर्शन शुरू हो गये हैं। संविधान निर्माण के साथ शुरू हुए यह प्रदर्शन संविधान के खिलाफ काम करने जैसा है, इसके लिए दर्जनों की संख्या में नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गये हैं।

हालांकि नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों ने संविधान बनने के इस एकपक्षीय निर्णय को जारी रखने का फैसला लिया और प्रत्येक जन के मन के मुताबिक काम किये जाने से मना किया है। इसी कारण नेपाल में भयावह स्थिति बनी हुई है।

यह नेपाल के राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह पता करें की कौन सी माँग उनके नागरिकों के हित से जुड़ी है और कौन सी नहीं। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद, नेपाल इस राय पर पहुँची है कि घरेलू समस्याओं के ठीक तरीके से ना सही कर पाना राजनीतिज्ञों की कूटनीतिक विफलता और अदूरदर्शिता को दिखाता है। नेपाल एक छोटा सा परिवार है और यहीं पर निवास करने वाले हिमल, पहड़ और तराई एक ही माँ के बेटे हैं। घर के किसी सदस्य को तकलीफ होती है तो परिवार के सभी लोग पीड़ा से कराह उठते हैं, यहीं वर्तमान स्थिति नेपाल की भी है।

हमारी सलाह ये है कि राज्य मधेशी आन्दोलन के सही व प्रमाणिक माँगों को बातचीत व सलाह–मश्वरा से निर्णय लें। और यदि कोई माँग गलत या राष्ट्र विरोधी हो तो उसे चिन्हित कर कारण सहित सभी के संज्ञान में उसका विरोध हो। हमारी सलाह है कि ऐसे लोकतांत्रिक और शान्तिपूर्ण कदम इस समस्या के समाधान के लिए उठाये जाने चाहिए, जो लम्बे समय तक चले। परिषद यह अपील करता है कि जल्द से जल्द प्रदर्शनकारी पार्टियाँ और समूह एकसाथ आयें और चर्चा करके बातचीत के द्वारा मधेशी समस्या का हल निकालें जिससे नागरिक सामान्य जीवन जी सकें।

परिषद यह अपील करता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता तराई जायें और नागरिकों से सीधे संवाद कर उसके समस्या का समाधान करें। ■

अभाविप ने कराया छात्राशक्ति का अहसास

मुरादाबाद। युवाओं के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विश्वसीय छात्र संगठन के तौर पर उभरा है। वर्तमान में 32 लाख से ज्यादा सदस्यता होना यह प्रमाणित करता है कि छात्र हितों के लिए काम करने वाले संगठन अभाविप पर छात्रों का भरोसा किस कदर कायम है। इसका स्पष्ट उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मंर भी देखने को मिला, जहाँ सभी सीटों पर विद्यार्थी परिषद का कब्जा हुआ। यह बातें संगठन की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने मेरठ प्रांत में हुए मुरादाबाद छात्रा सम्मेलन में छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहीं।

छात्राओं को उनकी शक्ति का अहसास कराते हुए ममता यादव ने कहा कि परिषद की पूरी सदस्यता में आठ लाख की संख्या छात्राओं की है। छात्रा प्रमुख की माने तो किसी भी देश या प्रदेश की परम्परा और संस्कृति वहां की महिलाओं से परिलक्षित होती है। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में लिखा हैय यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता। आदि से आज तक मानव–जीवन के विकास में उसकी महती भूमिका रही है।

राष्ट्रीय मंत्री अंजली चौहान ने कहा कि आज महिलाओं की स्थिति में सुधार व उनके सशक्तिकरण के विषय में सर्वत्र चिन्तन, मनन तथा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे समक्ष महिला सशक्तिकरण सबसे ज्वलंत विषय है। सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त कर उनकी प्रगति तथा विकास को सुनिश्चित करना है। अभाविप का मानना है कि महिलाएं जब तक हर क्षेत्र में मजबूत नहीं होंगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मन्त्री ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और सभ्यता के विकास के साथ–साथ महिलाओं की भूमिका में भी सकारात्मक परिवर्तन हुए है। आज नारी शिक्षा, राजनीति, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खेल, उद्योग, कला–संगीत, समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर रही हैं, वह कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है।

सम्मेलन में भारत के गौरवशाली अतित तथा छात्राओं के शैक्षिक और सामाजिकक स्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही साथ ईव टीजिंग पर रोक लगाने तथा कॉलेज के नजदीक सिनेमा घरों के पास दीवारों पर अश्लील पोस्टरों को हटवाने की भी माँग की गयी। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण के लिए 22 प्रांतों में आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों से महिलाओं में बढ़ी जागरुकता को भी बताया गया। कार्यक्रम में छह प्रांतों से 534 छात्राएं उपस्थित रही।

सम्मेलन के द्वितीय सत्र में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उपस्थित छात्राओं ने अपनी–अपनी शंका एवं समाधान प्रस्तुत किये। जिसमें प्रमुख रुप से छात्राओं की अनके समस्या समाधान में क्या भूमिका हो सकती है एवं उसे किस प्रकार से सम्पादित किया जा सकता है जैसै विषयों पर विचार हुआ। छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री रमेश गड़िया जी, प्रांत संगठन मंत्री नीतेश तोमर, अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने दिये। ■

भुवनेश्वर में अभाविप की महारैली

ओडिशा। गत दिनों भुवनेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया। इसमें ओडिशा के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। रैली को सम्बोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने कहा कि ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है। महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। शिक्षण संस्थानों में ढ़ांचागत सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

परिषद के प्रदेश सचिव प्रमोद राउत ने कहा कि अभाविप प्रदेश के छात्र–छात्राओं की समस्याओं को लेकर तब तक आन्दोलन करती रहेगी जब तक कि उनका समाधान नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की स्थिति ठीक नहीं है। विद्यालय, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, शिक्षकों के पदों को भरने के लिए राज्य सरकार कोई गंभीरता भी नहीं दिखा रही। इससे पहले, हजारों कार्यकर्ता स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कार्यालय से रैली निकालकर श्रीराम मन्दिर होते हुए लोवर पीएमजी पहुँचे। जिसके बाद अभाविप के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

गुजरात विश्वविद्यालय में छात्र हितों को लेकर प्रदर्शन

अहमदाबाद। छात्र हितों और उनके अधिकारों के लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुजरात विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की समस्याओं की अनदेखी किये जाने के विरोध में अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में मोर्चा खोला और कुलपति से मिलकर विभिन्न माँगों संबंधी ज्ञापन उन्हें सौंपा। इस दौरान, विद्यार्थी परिषद ने समस्याओं के निस्तारण के लिए एक माह का समय तय करते हुए कहा कि अगर इस अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल पाता तो अभाविप बड़े आन्दोलन को विवश होगी।

गुजरात विश्वविद्यालय में अभाविप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को अन्य कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भी समर्थन मिला। हेम चन्द्राचार्य नॉर्थ गुजरात विश्वविद्यालय में 650 से 700 की संख्या में छात्रों ने रैली में सहभागिता की। इस दौरान, राजकोट में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय में भी करीब 1200 की संख्या में छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया और मोर्चा निकाला। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न शैक्षिक एवं अकादमिक समस्याओं के निस्तारण की माँग की। साथ ही कहा कि अगर उनकी माँगों पर जल्द सुनवाई ना हुई और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान नहीं निकाले गये तो अभाविप प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेगी।

अभाविप द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय को सौंपे गये ज्ञापन में प्रमुख रूप से सेमेस्टर सिस्टम को बंद किया जाना, यूजीसी के नियमानुसार, 90 दिन के शैक्षणिक कार्य के बाद ही परीक्षा लिये जाने की बातें निहित हैं। साथ ही, छात्रों को नियमित तौर पर छात्रवृत्ति मिलने, परीक्षा के बाद पुनर्मूल्यांन की सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया, वार्षिक परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के मौजूद सिस्टम में बदलाव लाने संबंधी माँग को भी उठाया गया। इसके अलावा, अभाविप ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कॉलेज व विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जाने, कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और स्व–वित्त पोषित कॉलेजों के शुल्क का निर्धारण भी विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने को लेकर अपना ज्ञापन कुलपति को सौंपा। ■

राष्ट्र निर्माण की चिन्ता करें युवा - श्रीहरि बोरिकर

सिलीगुड़ी। 'भारत का गौरव तभी बढ़ेगा जब बंगाल का गौरव बढ़ेगा। एक समय बंगाल को भारत की शान कहा जाता था, वो स्थिति आज के समय में धूमिल है। पूर्व में देश में शिक्षा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं भी थी, जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला था। बंगाल की माटी में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने विचारों एवं उपलब्धियों से भारत को विश्व के मानचित्र पर प्रसिद्धि दिलायी। इतना ही नहीं, बंगाल की माटी से ही कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जन्म लिया, जिन्होंने देश को आजाद कराने में कुर्बानी दी।'

उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीहरि बोरिकर ने अभाविप की सिलीगुड़ी इकाई के बैनर तले 'मेक बेटर बंगाल फॉर बेटर इंडिया' विषय पर आयोजित 'थिंक इंडिया' सेमिनार में कहीं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बंगाल की शिक्षा और युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में अपना संगठन तैयार किया। स्वामी विवेकानन्द को अपना आदर्श माना। आज यह संगठन पूरे विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर उभरा है। चिन्ता इस बात की है कि जिस बंगाल में उसे इसकी प्रेरणा मिली आज वहीं के युवा राजनीति के शिकार होकर हिंसा के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभाविप हिंसा में विश्वास नहीं करती और अगर बंगाल साथ दे और यहाँ के युवा रचनात्मक कार्यों से जुड़ जायें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बन जायेगा। युवाओं को शिक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण पर चिन्ता करनी होगी। राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, युवाओं का चरित्र विकास कैसे हो इसके लिए हमेशा परिषद विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है।

सेमिनार में अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि बंगाल का गौरव वापस तभी बढ़ेगा जब शिक्षा बेहतर होगी। एकमात्र शिक्षा के बल पर ही बंगाल का गौरव वापस लौटेगा और बंगाल के गौरव से ही भारत का गौरव बढ़ेगा। सेमिनार के दौरान, बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (कोलकाता) के महासचिव सुपर्ण मैत्र, एशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक नीलेश अग्रवाल, अभाविप के बंगाल प्रांत के अध्यक्ष (कोलकाता) डॉ रमन कुमार त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री किशोर बर्मन एवं सेल्फ इंडस्ट्रीज क्रिएटर के प्रमुख सुमित कुमार घोष उपस्थित रहे। इसके अलावा, मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य टेक्निकल शिक्षण–संस्थानों व विभिन्न कॉलेजों से भारी तादाद में छात्र–छात्राएं शामिल हुए। ■

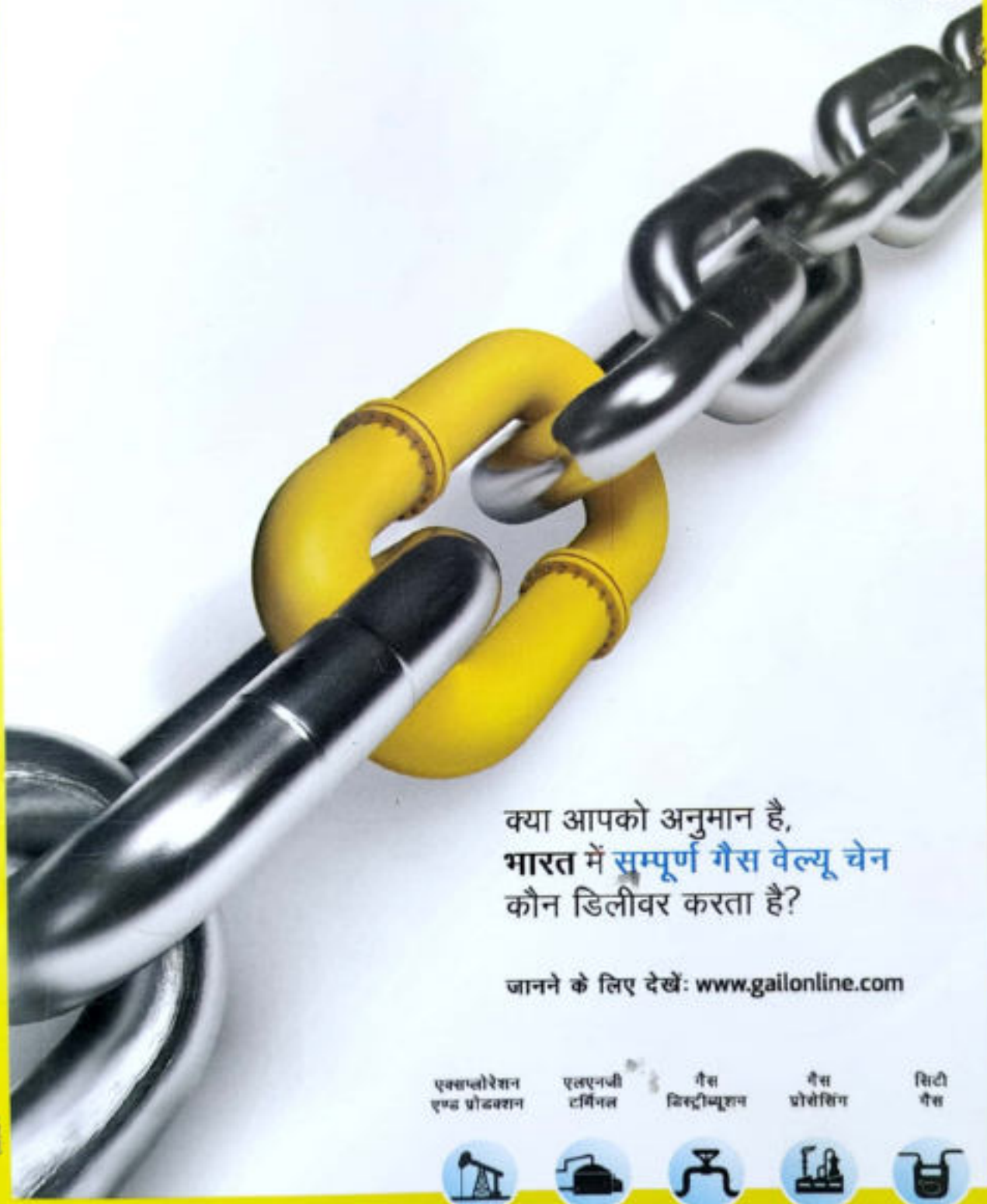

गेल
GAIL
गेल (इंडिया) लिमिटेड
भारत की
नम्बर 1
प्राकृतिक
गैस
कम्पनी
क्या आपको अनुमान है,
भारत में सम्पूर्ण गैस वेल्यू चेन
कौन डिलीवर करता है?
जानने के लिए देखें: www.gailonline.com
एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन
एलएनजी टर्मिनल
गैस डिस्ट्रीब्यूशन
गैस प्रोसेसिंग
सिटी गैस
/gailindia

Oil India Limited
OIL INDIA
Creating
OIL & GAS
Assets
for India's Energy Security
Oil India Limited [OIL], India's leading Navratna National Oil & Gas Company with strong Pan-India presence and a share of 9.48% of the country's crude oil production and 6.4% of natural gas production.
OIL's Mission is to be "The fastest growing energy company with global presence providing value to stakeholders."
OIL has been Conquering Newer Horizons with:
Overseas E&P assets and business in Libya, Gabon, Nigeria, Yemen, Venezuala, USA, Mozambique, Myanmar, Bangladesh & Russia.
Foray into Renewable Energy - Wind Energy Plants of installed capacity of 121.6 MW and Solar Power Plant of 5 MW.
International credit ratings - Moody's "BAA2" (higher than sovereign rating) and Fitch Rating "BBB-" (Stable) (equivalent to sovereign rating)
ऑयल इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
Oil India Limited
(A Government of India Enterprise)
Corporate Office : OIL House, Plot Number 19, Sector 16A, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh 201301, India
Tel: 0120-2419000, 2419200. Website : www.oil-india.com